



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 49]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 28, 2011/फाल्गुन 9, 1932

No. 49]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 28, 2011/PHALGUNA 9, 1932

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बजट प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 2011

सं. एफ. 2(13)-बी(डी)/2011.—निम्नलिखित को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :-

“बजट 2011-2012

वित्त मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी का भाषण

28 फरवरी, 2011

अध्यक्ष महोदया,

मैं वर्ष 2011-12 का केन्द्रीय बजट प्रस्तुत करने जा रहा हूँ।

हम एक असाधारण राजकोषीय वर्ष की समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। भूमंडलीकृत विश्व में तमाम अनिश्चितताओं और तेजी से हो रहे परिवर्तनों के बीच, यह वर्ष हमारे लिए कुछ अवसर और उनके चुनौतियाँ लेकर आया। इन सबके बीच हम राजकोषीय समेकन और उच्च आर्थिक विकास के सुविचारित पथ पर दृढ़ता से आगे बढ़े हैं।

2. वर्ष 2010-11 में हमारा विकास तीव्र और व्यापक रहा है। अर्थव्यवस्था संकट-पूर्व के विकास के पथ पर वापस आ गई है। कृषि में जहाँ फिर से वृद्धि दिखाई दी है, वहीं उद्योग जगत अपनी पूर्व तेजी पर लौट रहा है। सेवा क्षेत्र में लगभग दो अंकों की प्रगति बनी हुई है। राजकोषीय समेकन प्रभावशाली रहा है। इस वर्ष, उन निर्णायक संस्थागत सुधारों में भी उल्लेखनीय प्रगति दिखाई दी है जिनसे, निकट भविष्य में, दो अंकों की वृद्धि का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा।

3. हम जहाँ अनेक चिन्ताजनक क्षेत्रों का निराकरण करने में अच्छी प्रगति हासिल करने में सफल रहे हैं, वहीं कुछ अन्य मामलों में हम बेहतर कर सकते थे। कुल खाद्य मुद्रास्फीति फरवरी 2010 में 20.2 प्रतिशत पर पहुँच गयी थी जो घट कर जनवरी 2011 में आधे से कम 9.3 प्रतिशत पर आ गई है, परंतु यह अब भी चिन्ता का विषय बनी हुई है। मध्यावधि परिप्रेक्ष्य में, उच्च विकास के मार्ग पर बढ़ते रहने, विकास को अधिक समावेशी बनाने तथा अपनी संस्थाओं, सार्वजनिक वितरण और शासन पद्धतियों में सुधार लाने की हमारी तीन प्राथमिकताएं प्रासंगिक बनी हुई हैं। ये प्राथमिकताएं कुछ समय तक भारतीय नीति-निर्माताओं की प्रतिबद्धताएं बनी रहेंगी। तथापि, इन चुनौतियों के कुछ आयाम ऐसे हैं, जिन पर अल्पावधि में तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।

4. यद्यपि, हमने संकट-पूर्व की विकास की गति पुनः पकड़ ली है, फिर भी मांग और आपूर्ति पक्ष में वृद्धि की संरचना में तालमेल बैठाने की आवश्यकता है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि निजी खपत के साथ-साथ, निजी निवेश फिर से आता रहे और यह शीघ्रातिशीघ्र संकट-पूर्व की वृद्धि दरों के अनुरूप हो। इसके लिए निजी उद्यमों हेतु संसाधनों की गुंजाइश को बढ़ाने हेतु, दृढ़तर राजकोषीय समेकन और कुछ नीतिगत अड्चनों को दूर करने की आवश्यकता है। हमें बढ़ती हुई घरेलू मांग को पूरा करने के लिए कृषि जिसों की आपूर्ति में भी सुधार लाना होगा। इन दोनों मुद्दों पर, दृढ़संकल्प उपायों से मुद्रास्फीति प्रबन्धन संबंधी ढांचागत चिन्ताओं का निराकरण करने में मदद मिलेगी। इससे सतत उच्च वृद्धि हेतु एक अधिक स्थिर वृहत आर्थिक माहौल भी सुनिश्चित हो सकेगा।

5. संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों को संसाधनों की उपलब्धता में उल्लेखनीय सुधार किया है जिससे विकास प्रक्रिया

को अधिक से अधिक समावेशी बनाया जा सके। इसका प्रभाव हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की नई गतिशीलता में दिखायी दे रहा है। इससे भारत को वैश्विक आर्थिक मंदी के दलदल से तेजी से बाहर निकलने में मदद की है। फिर भी, अभी बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है - विशेषकर ग्रामीण भारत में, हमें पर्यावरण संबंधी वैद्य सरोकारों के आवश्यक विकास की जरूरतों के साथ तालमेल बैठाना होगा। इन सबसे ऊपर, युवा भारत की 'बढ़ती हुई आकांक्षाओं की चुनौती' है।

6. इन चिन्ताओं को दूर करने की दिशा में, मुझे संसाधनों की उपलब्धता कम से कम मध्यावधि में कोई बड़ी बाधा नहीं दिखाई देती है। तथापि, कार्यान्वयन की खामियां, लोक कार्यक्रमों से धन का अपव्यय और हमारे परिणामों की गुणवत्ता गम्भीर चुनौतियां हैं।

7. पिछले कुछ महीनों की कतिपय घटनाओं से शायद शासन में विपथन और सार्वजनिक जवाबदेही में कमी की छवि बनी होगी। सरकार व्यापक लोक हित में इनमें से कुछ घटनाओं से उत्पन्न होने वाली विशेष चिन्ताओं को दूर करने और विधि सम्मत शासन बनाए रखने के प्रति कटिबद्ध है, फिर भी ऐसी छवि बनना ठीक नहीं है। ये घटनाक्रम हमारे लिए हमारे नियामक मानकों और प्रशासनिक कामकाज में सुधार लाने का अवसर प्रदान करते हैं। प्रष्टाचार की समस्या का सामना हमें सामूहिक रूप से करना होगा।

8. एक जटिल और तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्था में, सरकार सम्पूर्ण ज्ञान की एकमात्र स्वामी होने का दावा नहीं कर सकती। वास्तव में, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में, इसे सदन के दोनों पक्षों के सहयोगियों से प्राप्त जानकारी का लाभ मिलता है। व्यापक राष्ट्रीय हित में उन्हें लोक नीतियों को प्रभावित करने में अपने विचारों और विशेषज्ञता का लाभ बांटना चाहिए। कुछ क्षेत्रों में, अच्छे परिणाम केन्द्र और राज्य सरकारों के समन्वित प्रयासों और कुछ अनुकूल वैदेशिक घटनाक्रमों पर निर्भर करते हैं।

9. मैं, 2011-12 के बजट को भारत में एक अधिक पारदर्शी और परिणामोन्मुख आर्थिक प्रबन्धन प्रणाली दिशा में बढ़ते कदम के रूप में देखता हूँ। हम कराधान, व्यापार और टैरिफों तथा सामाजिक अंतरणों को सरल बनाने और उन्हें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में रखने, विकेकाधिकार और नौकरशाही के विलम्बों से मुक्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपाय कर रहे हैं। इससे एक नई, जीवन्त और अधिक सक्षम अर्थव्यवस्था के लिए मार्ग प्रशस्त होगा।

10. कई बार सबसे बड़े सुधार वे नहीं होते, जो समाचार पत्रों की सुखिया बनते हैं, बस वे होते हैं जो आम आदमी के दिन-प्रतिदिन की जिन्दगी को प्रभावित करने वाले शासन के क्रियाकलापों से सम्बन्धित होते हैं। इस वर्ष का बजट तैयार करते समय, मैंने इस तथ्य को पूरी तरह अपने जेहन में रखा है। मैं अपने प्रयास में माननीय प्रधानमंत्री के कुशल मार्गदर्शन और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी द्वारा दिए गए भरपूर समर्थन के लिए उनका आभारी हूँ। मैं, अब, अर्थव्यवस्था के संक्षिप्त सिंहावलोकन से आरम्भ करूंगा।

1. अर्थव्यवस्था का सिंहावलोकन

11. गत शुक्रवार को, मैंने सदन के पटल पर 2010-11 की आर्थिक समीक्षा प्रस्तुत की थी। इसमें पिछले 12 महीनों के दौरान देश

की आर्थिक स्थिति का विस्तृत विश्लेषण दिया गया है। 2010-11 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में वस्तुतः 8.6 प्रतिशत वृद्धि होने का अनुमान है। 2010-11 में, कृषि में 5.4 प्रतिशत, उद्योग में 8.1 प्रतिशत और सेवाओं में 9.6 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है। ये सभी सेक्टर विकास के सुदृढीकरण में योगदान कर रहे हैं। अधिक महत्वपूर्ण यह है कि अर्थव्यवस्था ने वैदेशिक और घरेलू दोनों झटकों से उबरने में असाधारण समुत्थान शक्ति दर्शायी है।

12. इस वर्ष हमारी मुख्य चिन्ता खाद्य वस्तुओं की कीमतों में निरंतर बढ़ोत्तरी रही है। मुद्रास्फीति दो अलग-अलग चरणों में दिखाई पड़ी है। वर्ष के आरंभ में, कुछ अनाजों, चीनी और दालों में खाद्य मुद्रास्फीति उच्च रही। वर्ष की दूसरी छमाही में, जब इन वस्तुओं की कीमतें कम हुईं और मुद्रास्फीति की ऋणात्मक दरें भी दर्ज हुईं तो प्याज, दूध, कुक्कुट एवं कुछ सब्जियों और अन्य वस्तुओं की कीमतों में उछाल आ गया। हाल में थोक बाजारों में प्याज की कीमतों में भारी गिरावट आई है और हमें इनके निर्यात पर लगा प्रतिबंध हटाना पड़ा है।

13. अधिकांश खाद्य वस्तुओं की उपलब्धता में सुधार आने के बावजूद, उपभोक्ताओं की कीमतों की मौसमी गिरावट, जो सामान्यतः शीतकालीन महीनों में दिखाई पड़ती है का फायदा नहीं मिला। इन घटनाक्रमों से वितरण और विपणन प्रणालियों में खामियों का पता चला। ये खामियां बढ़ते आय स्तरों से इन खाद्य वस्तुओं की बढ़ती मांग के कारण बढ़ती जा रही हैं। थोक और खुदरा कीमतों के बीच तथा देश के अलग-अलग भागों के बाजारों में अत्यधिक अंतर कतई स्वीकार्य नहीं है। ऐसा किसानों को मिलने वाली उचित कीमतों और उपभोक्ताओं को मिलने वाली प्रतिस्पर्धी कीमतों के खर्च पर हो रहा है।

14. राजकोषीय नीति का समर्थन करते हुए, 2010-11 में उठाए गए मौद्रिक नीतिगत कदमों से मुख्य (कोर) मुद्रा स्फीति को काबू में रखने में सफलता मिली है। चूँकि मौद्रिक नीति के पारेषण में समय लगेगा, अतः मैं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पहले ही किए गए उपायों से आने वाले महीनों में मुद्रास्फीति में और कमी आने की उम्मीद करता हूँ।

15. मौजूदा वर्ष में भारत के वैदेशिक क्षेत्र संबंधी घटनाक्रम उत्साहजनक रहे हैं। यहां तक कि विकसित देशों में सुधार धीरे-धीरे हो रहा है, हमारे व्यापार निष्पादन में सुधार हुआ है। अप्रैल-जनवरी, 2010-11 के दौरान, विगत वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले, निर्यात 29.4 प्रतिशत बढ़कर 184.6 बिलियन अमरीकी डॉलर और आयात 17.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज कर 273.6 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया है। चालू खाता घाटा 2009-10 के स्तर के आस-पास है और इसके वित्तपोषण की संरचना के कारण कुछ चिन्ताएं हुई हैं।

16. वैश्वीकृत विश्व में नीति निर्माण करते समय संभावित अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों को ध्यान में रखना पड़ता है। वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए, यह महत्वपूर्ण है कि हमारे निवेशकों, उद्यमियों और उपभोक्ताओं की अर्थव्यवस्था की वृहत आर्थिक संभावनाओं में समाभिरूपता हो। इस पृष्ठभूमि में, 2011-12 में भारतीय अर्थव्यवस्था के ± 0.25 प्रतिशत के बाह्य बैंड के साथ 9 प्रतिशत की वृद्धि होने की प्रत्याशा है। मैं अगले वर्ष औसत मुद्रास्फीति और

चालू खाता घाटा कम होने की उम्मीद करता हूँ जिनमें उच्च घरेलू बचत दर और स्थिर पूंजीगत प्रवाहों से बेहतर प्रबंधन हो सकेगा। विगत वर्ष की भांति, मैं इस वर्ष भी इंद्र भगवान की समय पर कृपा चाहता हूँ जिससे प्रचुर मात्रा में मॉनसूनी वर्षा हो और इसी तरह मैं देवी लक्ष्मी से भी प्रार्थना करता हूँ। मेरा विचार है कि किसी के जोखिमों के प्रति ध्यान बंटाने की यह एक अच्छी कार्यनीति है।

II. सतत विकास

17. पिछले बजट में, मैंने 2008-09 और 2009-10 के दौरान भारत में आर्थिक मंदी के संबंध में वैश्विक वित्तीय संकट के प्रभाव को कम करने हेतु दिए गए राजकोषीय प्रोत्साहन पैकेज को वापस लेना आरम्भ किया था। इस वर्ष, मैं उस मार्ग पर आगे बढ़ गया हूँ। मुझे विश्वास है कि वर्तमान पुनरुत्थान के एक भाग को भविष्य की समुत्थान-शक्ति के निर्माण के लिए अलग रखा जाना चाहिए। वास्तव में एक प्रतिचक्रीय राजकोषीय नीति विदेशी झटकों और स्थानीय घरेलू घटकों के प्रति हमारा सर्वोत्तम बीमा होती है।

राजकोषीय समेकन

18. केन्द्र में राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 (एफआरबीएम अधिनियम) और राज्य स्तर के तदनुसूची अधिनियमों से यह पता चलता है कि सांविधिक राजकोषीय समेकन लक्ष्यों का अर्थव्यवस्था के वृहत आर्थिक प्रबंधन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। केन्द्र सरकार इस वर्ष एफआरबीएम अधिनियम, में एक संशोधन लाएगी जिसमें अगले पांच वर्षों के लिए राजकोषीय खाका तैयार किया जाएगा।

19. तेरहवें वित्त आयोग ने राज्यों के लिए राजकोषीय समेकन की एक रूपरेखा तैयार की है जिसमें उनसे 2014-15 तक हर हालत में राजस्व घाटा समाप्त करने और राजकोषीय घाटे को अपने सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत तक लाने की अपेक्षा की गयी है। इसमें यह भी सिफारिश की गई है कि इस अवधि के दौरान स.घ.उ. के 24.3 प्रतिशत का संयुक्त राज्य ऋण लक्ष्य हासिल किया जाए। राज्यों के लिए यह अपेक्षित है कि वे इन सिफारिशों के अनुरूप अपने एफआरबीएम अधिनियमों में संशोधन करें अथवा इन्हें अधिनियमित करें।

20. सरकार वित्त मंत्रालय में एक स्वतंत्र ऋण प्रबंधन कार्यालय की स्थापना की प्रक्रिया में लगी हुई है। एक मिडल कार्यालय पहले से ही कार्य कर रहा है। अगले कदम के रूप में, मैं आगामी वर्ष में भारतीय लांक ऋण प्रबंधन अधिकरण विधेयक लाने का प्रस्ताव करता हूँ।

कर सुधार

21. प्रत्यक्ष-कर संहिता (डीटीसी) का प्रारंभ और प्रस्तावित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से एक निर्णायक मोड़ आया। इन सुधारों के फलस्वरूप, दरों में संतुलन, विधियों का सरलीकरण और बेहतर अनुपालन होगा।

22. जैसा कि माननीय सदस्यों को पता है, प्रत्यक्ष कर संहिता विधेयक संसद में अगस्त, 2010 में प्रस्तुत किया गया था। स्थायी समिति की रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात् हम 2011-12 में इस संहिता

को इसके अधिनियमन के लिए अंतिम रूप दे सकेंगे। यह सहभागिता विधान में अग्रणी प्रयास रहा है। इस संहिता के 1 अप्रैल, 2012 से प्रभावी होने का प्रस्ताव है जिससे करदाताओं, व्यवसायियों और प्रशासकों को इस विधान को पूरी तरह समझने और संशोधित प्रक्रियाओं के अनुसार समायोजित करने में आसानी होगी।

23. प्रत्यक्ष कर संहिता से भिन्न, वस्तु एवं सेवा कर पर निर्णय राज्यों की सहमति से लिए जाने हैं क्योंकि पिछले चार वर्षों में राज्यों के साथ हमारी बातचीत में पर्याप्त प्रगति हुई है। मतभेद के क्षेत्र कम हुए हैं। वस्तु एवं सेवा कर को लागू करने के एक उपाय के रूप में, मैं संसद के इस सत्र में संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत करने का प्रस्ताव करता हूँ। केन्द्र और राज्य वस्तु एवं सेवा कर के लिए माडल विधान का प्रारूप तैयार करने की प्रक्रिया भी चल रही है।

24. वस्तु एवं सेवा कर को प्रारंभ करने के लिए उठाए जा रहे अन्य उपायों में ठोस आईटी अवसरचना की स्थापना करना भी शामिल है। हमने वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क में महत्वपूर्ण प्रगति की है। पंजीकरण, प्रतिलाभ तथा भुगतानों की महत्वपूर्ण व्यावसायिक प्रक्रियाएं पूर्ण होने के अन्तिम चरण में हैं। राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड (एनएसडीएल) को राष्ट्रीय सूचना उपयोगिता में शामिल करने हेतु प्रौद्योगिकी भागीदार के रूप में चुना गया है। यह वस्तु एवं सेवा कर के सम्बन्ध में आईटी आधार की स्थापना तथा उसका संचालन करेगा। जून, 2011 तक, एनएसडीएल सम्पूर्ण देश में इसके लागू होने से पहले ग्यारह राज्यों के सहयोग से एक पायलट पोर्टल की स्थापना करेगा।

व्यय सुधार

25. लोक व्यय का प्रभावी प्रबन्धन राजकोषीय समेकन प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। यह अधिक महत्वपूर्ण नहीं है कि हम क्या खर्च करते हैं, बल्कि हम कैसे खर्च करते हैं, यह महत्वपूर्ण है। व्यय सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन परक होगा। आयोजना, आयोजना-भिन्न राजस्व तथा पूंजी व्यय के मौजूदा वर्गीकरण पर नए सिरे से विचार करने की आवश्यकता है। यह आवश्यक है क्योंकि हर कोई हमारे विकास हेतु सेवा क्षेत्र और ज्ञान अर्थव्यवस्था की महत्ता को मानता है। इन मुद्दों की जांच करने हेतु योजना आयोग द्वारा डॉ. सी. रंगराजन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है।

सब्सिडी

26. 2010-11 के दौरान, पोषण आधारित सब्सिडी नीति को, यूरिया को छोड़कर, सभी उर्वरकों के सम्बन्ध में सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया, सभी हितधारकों ने इस नीति का स्वागत किया है, और उर्वरकों की उपलब्धता में सुधार हुआ है। यूरिया को शामिल करने के लिए पोषक आधारित सब्सिडी व्यवस्था विस्तारित करने के प्रति सरकार गम्भीरता से विचार कर रही है।

27. सरकार विशेष कर, ईंधन तथा खाद्यान्न पर सब्सिडी प्रदान करती है ताकि आम आदमी को वहनीय कीमतों पर इन बुनियादी आवश्यकताओं की पहुंच सुनिश्चित हो सके। सब्सिडी प्राप्त ईंधन की भारी मात्रा लक्षित लाभार्थियों तक नहीं पहुंचती है और सब्सिडी प्राप्त मिट्टी का तेल भारी मात्रा में अन्यत्र चला जाता है। हाल में घटित दुखद घटना से यह प्रकट हुआ है। हमने काफी अर्से से सम्बद्ध लाभार्थियों हेतु सब्सिडियों के कार्यान्वयन के तौर तरीकों पर

विचार विमर्श किया है। हमारी चर्चा से निर्णय लेने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। मिट्टी के तेल तथा उर्वरक दोनों के सम्बन्ध में बेहतर-क्षमता, किफायती लागत एवं बेहतर वितरण का सुनिश्चय करने हेतु, सरकार चरणबद्ध तरीके से गरीबी की रेखा से नीचे के लोगों को नकद सब्सिडी सीधे देने की दिशा में अग्रसर होगी।

28. श्री नन्दन नीलेकानी की अध्यक्षता में मिट्टी का तेल, एलपीजी तथा उर्वरकों के सम्बन्ध में सब्सिडी सीधे देने की प्रस्तावित प्रणाली के तौर तरीकों को तैयार करने हेतु एक कार्यबल का गठन किया गया है। कार्यबल की अन्तरिम रिपोर्ट जून 2011 तक प्राप्त होने की आशा है। यह प्रणाली मार्च 2012 तक प्रभावी हो जाएगी।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में लोगों का स्वाभित्व

29. केन्द्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में स्वाभित्व का आधार-व्यापक बनाने के सरकार के कार्यक्रम को काफी अच्छा रेटिंग मिला है। केन्द्र सरकार के सरकारी क्षेत्र के उद्देश्यों की यह पब्लिक इश्यू ने मौजूदा वित्त वर्ष में लगभग 50 लाख छूटरी निवेशकों को आकर्षित किया है।

30. सरकार 2010-11 में, 40,000 करोड़ रुपये के लक्ष्य की तुलना में, विनिवेश से लगभग 22,144 करोड़ रुपये जुटाएगी। कर-भिन राजस्व में आशा से अधिक वसूली हो जाने से मौजूदा वर्ष के लिए योजना बनाए गए विनिवेश मुद्दों में से कुछ की नए सिरे से योजना बनानी पड़ी। मैं, 2011-12 में 40,000 करोड़ रुपये जुटाकर विनिवेश की इस गति को बनाए रखने का प्रस्ताव करता हूँ। यहाँ मैं इस बात को दोहराना चाहूँगा कि सरकार सरकारी क्षेत्र के केन्द्रीय उपक्रमों के स्वाभित्व तथा प्रबन्धन नियंत्रण को कम से कम 51 प्रतिशत पर बनाए रखने हेतु प्रतिबद्ध है, जैसा कि मेरे 2009-10 के बजट भाषण में कहा गया था।

निवेश माहौल

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश

31. एफडीआई नीति को और अधिक प्रयोक्ता अनुकूल बनाने के लिए पूर्व के सभी विनियमों तथा दिशा-निर्देशों को एक व्यापक दस्तावेज में संकलित किया गया है और जिसकी प्रत्येक छह मास में समीक्षा होती है। पिछली समीक्षा सितम्बर 2010 में की गयी थी। यह समीक्षा सुस्पष्टता बढ़ाने तथा विदेशी निवेशकों के प्रति हमारी विदेशी प्रत्यक्ष नीति का पूर्वानुमान लगाने के विशिष्ट आशय से की गयी थी। एफडीआई नीति को और उदार बनाने के लिए विचार-विमर्श किया जा रहा है।

विदेशी संस्थागत निवेशक

32. वर्तमान में, केवल विदेशी संस्थागत निवेशकों के उप-खाले सेबी के पास पंजीकृत होते हैं और एनआरआई को म्यूचुअल फंड योजनाओं में निवेश की अनुमति दी जाती है। पोर्टफोलियो निवेश माध्यम को उदार बनाने हेतु, सेबी पंजीकृत म्यूचुअल फंडों को इक्विटी योजनाओं के लिए कंवाईसी आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विदेशी निवेशकों से अभिदान स्वीकार करने की अनुमति देने का निश्चय किया गया है। इससे भारतीय म्यूचुअल फंड तक सीधी पहुँच

बढ़ाने और भारतीय इक्विटी बाजार में विदेशी निवेशकों की श्रेणी को व्यापक बनाने में सक्षम होंगे।

33. अवसंरचना क्षेत्र निधियों का प्रवाह बढ़ाने के लिए अवसंरचना क्षेत्र में पांच वर्षों से अधिक की अवशिष्ट परिपक्वता अवधि वाले कम्पनियों द्वारा जारी कारपोरेट बांडों में निवेश की एफआईआई सीमा को 20 बिलियन अमरीकी डालर की अतिरिक्त सीमा से बढ़ाकर 25 बिलियन अमरीकी डालर कर दिया गया है। इससे एफआईआई के लिए कारपोरेट बांडों में निवेश हेतु उपलब्ध कुल सीमा बढ़कर 40 बिलियन अमरीकी डालर हो जाएगी। चूंकि अधिकांश अवसंरचना सम्बन्धी कम्पनियाँ एसपीवी के स्वरूप में नियोजित हैं। एफआईआई को भी न्यूनतम तीन वर्षों की समयबंदी सहित असूचीबद्ध बांडों में निवेश की अनुमति होगी। तथापि, एफआईआई की समयबंदी के दौरान स्वयं आपस में व्यापार करने की अनुमति होगी।

वित्तीय क्षेत्र विधायी पहल

34. 1990 के दशक के प्रारम्भ में शुरू किए गए वित्तीय क्षेत्र संबंधी सुधारों से भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अच्छे परिणाम निकले हैं। संग्रह सरकार इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। तदनुसार, मैं वित्तीय क्षेत्र में निम्नलिखित विधान लाने का प्रस्ताव करता हूँ :

- (i) बीमा निधि (संशोधन) विधेयक, 2008;
- (ii) जीवन बीमा निधम (संशोधन) विधेयक, 2009;
- (iii) संशोधित पेंशन निधि विधेयक और विकास प्राधिकरण विधेयक, 2005 में पहली बार प्रस्तुत;
- (iv) बैंकिंग विधि संशोधन विधेयक, 2011
- (v) आड़ती और प्राप्तियों का समनुदेशन विधेयक;
- (vi) भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक विधि) संशोधन विधेयक, 2009; और
- (vii) आरडीबीएफआई अधिनियम, 1993 और एसएआरएफआईएसआई अधिनियम, 2002 में संशोधन हेतु विधेयक।

35. मैंने अपने पिछले बजट में घोषणा की थी कि भारतीय रिजर्व बैंक निजी क्षेत्र के भागीदारों को कुछ अतिरिक्त बैंकिंग लाइसेंस प्रदान करने के बारे में विचार करेगा। तदनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक ने अगस्त 2010 में एक परिचर्चा पत्र जारी किया था, जिसमें आम लोगों से जानकारी मांगी गयी थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग विनियामक अधिनियम में कुछ संशोधनों का प्रस्ताव किया है। मैं, इस बजट सत्र में, इस सम्बन्ध में कुछ उपयुक्त विधायी संशोधन लाने का प्रस्ताव करता हूँ। भारतीय रिजर्व बैंक इस वित्त वर्ष की सम्पत्ति से पहले बैंकिंग लाइसेंसों हेतु दिशा-निर्देश जारी करने की योजना बना रहा है।

सार्वजनिक क्षेत्र बैंक पुनःपंजीकरण

36. वर्ष 2010-11 के दौरान, सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 20,157 करोड़ रुपये की राशि मुहैया करा रही है ताकि जोखिम भारित, पूंजी आस्ति अनुपात (सीआरएआर) को 8 प्रतिशत पर रखा जा सके तथा कुछ बैंकों में सरकारी इक्विटी को बढ़ाकर 58 प्रतिशत किया जा सके। मैं, 2011-12 हेतु 6000 करोड़ रुपये की

राशि की व्यवस्था करने का प्रस्ताव करता हूँ ताकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक 8 प्रतिशत पर न्यूनतम टीयर-1 सीआरएआर रखने में सक्षम हों।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पुनः पुंजीकरण

37. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की वित्तीय सुदृढ़ता के भाग के रूप में इस वर्ष इन बैंकों को 350 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गयी थी। मैं 2011-12 के लिए 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था का प्रस्ताव करता हूँ ताकि वे 31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार कम से कम 9 प्रतिशत पर सीआरएआर रखने में समर्थ हों।

माइक्रो वित्त संस्थाएं

38. माइक्रो वित्त संस्थाएं (एमएफआई) वित्तीय समावेशन के महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में उभरे हैं। अपेक्षाकृत छोटी माइक्रो वित्त संस्थाओं को इक्विटी तथा अर्द्ध-इक्विटी उपलब्ध कराने हेतु समर्पित निधि के सृजन से विकास बनाए रखने तथा प्रचालनों में मानदंड एवं प्रभावकारिता प्राप्त करने में मदद मिलेगी। मैं, इस वर्ष सिडबी के साथ 100 करोड़ रुपए की "भारत माइक्रो वित्त इक्विटी निधि" का सृजन करने का प्रस्ताव करता हूँ। महिलाओं को सशक्त बनाने तथा इन स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) के संवर्धन के लिए 500 करोड़ रुपए की राशि से, मैं, महिला स्व-सहायता समूह विकास निधि के सृजन का प्रस्ताव करता हूँ। भारत में माइक्रो वित्त क्षेत्र से संबंध मुद्दों की जांच करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्थापित की गयी समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। सरकार, लघु उधारकर्ताओं के हितों की रक्षा हेतु, उपयुक्त विनियामक फ्रेमवर्क लाने पर विचार कर रही है।

ग्रामीण अवसंरचना विकास विधि

39. ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) बैंक निधियों को ग्रामीण अवसंरचना के वित्त पोषण हेतु लगाने का एक प्रमुख माध्यम है। यह राज्य सरकारों के बीच लोकप्रिय है। मैं आरआईडीएफ-XVII की मूल निधि को मौजूदा वर्ष में 16,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2011-12 में 18,000 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव करता हूँ। यह अतिरिक्त आवंटन भांडागार सुविधाओं के सृजन हेतु समर्पित होगा।

माइक्रो-लघु एवं मध्यम उद्यम

40. माइक्रो तथा लघु उद्यम साम्य तथा समावेशी विकास के उद्देश्यों को पुष्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पिछले वर्ष सिडबी को 4,000 करोड़ रुपए इन उद्यमों हेतु बैंकों द्वारा वृद्धिशील उधार के पुनः वित्त पोषण हेतु प्रदान किए गए थे। वर्ष 2011-12 के लिए मैं, सिडबी को इसी प्रयोजनार्थ ऐसे बैंकों को 5,000 करोड़ रुपए उपलब्ध कराने का प्रस्ताव करता हूँ जिन्होंने प्राथमिक क्षेत्र के उधार लक्ष्यों में गिरावट दर्ज की थी।

41. हथकरघा बुनकर आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। परिणामस्वरूप, उनमें से अनेक हथकरघा बुनकर सहकारी सोसाइटियों को जो वित्तीय दृष्टि से अक्षम हो चुकी हैं, को ऋण नहीं चुका पाए हैं। मैं, नाबार्ड को इन सहकारी समितियों को सहायता प्रदान करने हेतु 3,000 करोड़ रुपए चरणों में उपलब्ध कराने का प्रस्ताव करता हूँ। इस पहल से 15,000 सहकारी सोसाइटियां तथा लगभग 3 लाख

हथकरघा बुनकर लाभान्वित होंगे। वस्त्र मंत्रालय इस योजना का ब्यौरा योजना आयोग से परामर्श करके तैयार करेगा।

42. मुझे यह सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि अल्पसंख्यक समुदायों के बकाया ऋण जो पिछले वर्ष की समाप्ति पर कुल प्राथमिक क्षेत्र उधार का 13 प्रतिशत थे, मौजूदा वर्ष में बढ़कर 13.6 प्रतिशत हो गए हैं। मैंने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को आदेश दिए हैं कि वे जितनी जल्दी संभव हो 15 प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त करें।

आवास क्षेत्र वित्त

43. आवास क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने हेतु, मैं, आवास ऋणों पर 1 प्रतिशत की ब्याज आर्थिक सहायता की मौजूदा योजना को उस स्थिति में 15 लाख रुपए तक के आवास ऋण तक बढ़ाकर उधार बना रहा हूँ जहां मकान की लागत क्रमशः 10 लाख रुपए तथा 20 लाख रुपए की मौजूदा सीमा से बढ़ाकर 25 लाख रुपए से अधिक न हो।

44. शहरी क्षेत्रों में आवासीय सम्पत्तियों की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण, मैं, प्राथमिक क्षेत्र ऋण के अन्तर्गत मौजूदा आवास ऋण सीमा को 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए करने का प्रस्ताव करता हूँ।

45. ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धी दरों पर लक्षित समूहों के लिए आवास वित्त पोषण की व्यवस्था करने हेतु, मैं ग्रामीण आवास निधि के अंतर्गत इस प्रावधान को 2,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 3,000 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव करता हूँ।

46. आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों और एलआईजी परिवारों के लिए ऋण प्राप्त करना एक बड़ी चुनौती है। इस मुद्दे के समाधान हेतु, मैं राजीव आवास योजना के तहत बंधक जोखिम गारंटी निधि के सृजन का प्रस्ताव करता हूँ। यह आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों और एलआईजी परिवारों द्वारा लिए गए ऋणों पर गारंटी प्रदान करेगी तथा उनकी ऋण क्षमता को बढ़ाएगी।

47. ऋण मामलों में धोखाधड़ी, जिनमें एक ही अचल सम्पत्ति पर विभिन्न बैंकों से एक से अधिक बार ऋण देना शामिल है, को रोकने के लिए, सरकार ने एसएआरएफईएसआई अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्री की स्थापना को सुसाध्य बनाया है। यह रजिस्ट्री 31 मार्च, 2011 तक काम करने लगेगी।

वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग

48. बजट 2010-11 में की गई घोषणा के अनुसरण में, सरकार ने न्यायमूर्ति बी. एन. श्री कृष्णा की अध्यक्षता में एक वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग की स्थापना की है। यह वित्तीय क्षेत्र के कानूनों, नियमों और विनियमों का पुनर्लेखन और सुप्रवाहीकरण करेगा और उन्हें आधुनिक वित्तीय क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाएगा। यह आयोग 24 महीनों में अपना कार्य पूरा करेगा।

49. संसद में 2009 में प्रस्तुत कंपनी विधेयक संसदीय स्थाई समिति से प्राप्त हो चुका है। प्रस्तावित विधेयक मौजूदा सत्र में लोक सभा में पेश किया जाएगा।

कृषि

50. कृषि का विकास हमारी विकास कार्यनीति का केन्द्र बिन्दु है। चालू वर्ष के दौरान किए गए उपायों ने कृषि तथा कृषि-प्रसंस्करण कार्यकलापों में निजी निवेश आकर्षित करना शुरू किया है। इस प्रक्रिया को और गहन किया जाना है।

51. 2010-11 के बजट में, मैंने कृषि उत्पादन, कृषि उपज की बर्बादी में कमी, किसानों को ऋण सहायता और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र पर जोर देने को समाहित करते हुए, एक चार-स्तरीय कार्ययोजना प्रस्तुत की थी। इन कार्यक्रमों के परिणाम मिलने शुरू हो गये हैं परन्तु हमारी खाद्य अर्थव्यवस्था में अन्य मुद्दे भी हैं, जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। खाद्य मूल्यों में हाल की तेजी फलों और सब्जियों, दूध, मांस, कुक्कट, अंडे और मछली, जैसी वस्तुओं जो प्राथमिक खाद्य वस्तुओं के लिए थोक मूल्य सूचकांक समूह का 70 प्रतिशत बनता है, के मूल्यों में वृद्धि की वजह से थी। इस वर्ष मेरा ध्यान वस्तुओं के लिए उत्पादन और वितरण की बाधाओं को दूर करने पर केन्द्रित रहेगा। मैं जल्दी शुरुआत के लिए इस समय चल रही राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अधीन इन योजनाओं के लिए आवंटन करने का प्रस्ताव करता हूँ। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का कुल आवंटन 2010-11 में 6,755 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2011-12 में 7,860 करोड़ रुपए किया जा रहा है।

पूर्वी क्षेत्र में हरित क्रान्ति लाना

52. पूर्वी क्षेत्र में हरित क्रान्ति आने को है। इस क्षेत्र की संभाव्यता को साकार करने के लिए, पिछले वर्ष का कार्यक्रम 2011-12 में जारी रहेगा और इस निमित्त 400 करोड़ रुपए का और आवंटन किया जाएगा। इस कार्यक्रम का लक्ष्य असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चावल आधारित फसल प्रणाली में सुधार करना है।

वर्षासिंचित क्षेत्रों में 60,000 दलहन ग्रामों का एकीकृत विकास

53. दलहन पर सरकार की पहल की किसानों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। द्वितीय अग्रिम अनुमानों के अनुसार, इस वर्ष दालों का उत्पादन 165 लाख टन होने की संभावना है, जबकि पिछले वर्ष यह 147 लाख टन हुआ था। इन लाभों में और बढ़ोतरी करते हुए हमें अगले तीन वर्षों में, दालों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। मैं फसल उत्पादकता बढ़ाने एवं बाजार संपर्कों को मजबूत करने के लिए वर्षासिंचित क्षेत्रों में 60,000 दलहन ग्रामों को प्रोत्साहित करने के लिए 300 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध करने का प्रस्ताव करता हूँ।

ऑयल पाम का संवर्धन

54. खाद्य तेलों का घरेलू उत्पादन मांग का केवल लगभग 50 प्रतिशत ही पूरा हो पाता है। आपूर्ति की इस कमी को आयातों से पूरा किया जाता है जो हमारी आवश्यकता की मात्रा के कारण प्रायः उच्च मूल्यों पर किए जाते हैं। हमारे हाल के उपायों और अच्छी वर्षा होने से, तिलहन का उत्पादन, 2009-10 में 249 लाख टन की तुलना में, 2010-11 में 278 लाख टन होने की संभावना है। खाद्य तेलों की कमी को दूर करने के लिए हमें ऑयल पाम पर विशेष ध्यान देना होगा क्योंकि यह सर्वाधिक सक्षम तिलहनी फसलों में एक है। मैं, किसानों को बाजारों के साथ जोड़कर ऑयल पाम पौध रोपण के अधीन 60,000 हेक्टेयर लाने हेतु 300 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान करने का प्रस्ताव करता हूँ। इस कार्यक्रम से पांच वर्षों में लगभग 3 लाख मीट्रिक टन पाम ऑयल वार्षिक रूप से प्राप्त होगा।

सब्जी समूह संबंधी कार्यक्रम

55. सब्जियों की बढ़ती हुई मांग को उत्पादकता और बाजार सम्यकों में जबर्दस्त वृद्धि करके पूरा किया जाना है। क्वालिटी सब्जियाँ प्रतिस्पर्धी मूल्यों पर उपलब्ध कराने हेतु एक सक्षम आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करनी होगी, मैं, किसानों के लिए उत्पादन और आय के लाभकारी विचार को कार्यरूप देने के लिए सब्जी कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु 300 करोड़ रुपए देने का प्रस्ताव करता हूँ। आरंभ में, यह कार्यक्रम प्रमुख शहरी केन्द्रों के निकट शुरू किया जाएगा। पोषक अनाज

56. हम जहां सब्जी के लिए भोजन सुनिश्चित करते हैं, वहीं हमें संतुलित पोषाहार को भी बढ़ावा देना चाहिए। बाजरा, ज्वार, रागी और अन्य मोटे अनाज अत्यंत पौष्टिक हैं और ये अनेक औषधीय गुणों के कारण जाने जाते हैं। तथापि, इन पोषक अनाजों की उपलब्धता और खपत कम है और हाल के वर्षों में इसमें निरंतर कमी आई है। इन अनाजों के अधिक उत्पादन को बढ़ावा देने, उनकी प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियों के उन्नयन और उनसे स्वास्थ्य को होने वाले फायदों के बारे में जागरूकता पैदा करने हेतु 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा रहा है। इस पहल से देश के शुष्क और अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में मोटे अनाजों का उत्पादन करने वाले दस लाख किसानों को बाजार सम्बद्ध उत्पादन सहायता उपलब्ध होगी। यह कार्यक्रम लगभग 25,000 ग्रामों को शामिल करते हुए 1,000 सुसम्बद्ध प्रखंडों में आरंभ किया जाएगा। इसमें पौषाहार संबंधी सुरक्षा में सुधार लाने और पशुओं के लिए दाना और चारा आपूर्ति में सुधार लाने में मदद मिलेगी।

राष्ट्रीय प्रोटीन सम्पूर्ण मिशन

57. पशु जन्य प्रोटीन और अन्य पोषण तत्वों से भरपूर खाद्यान्नों की खपत में हाल ही में वृद्धि हुई है, जिसमें मांग उत्पादन की अपेक्षा तेजी से बढ़ रही है। 2011-12 में 300 करोड़ रुपए के आवंटन से राष्ट्रीय प्रोटीन सम्पूर्ण मिशन आरम्भ किया जा रहा है। इसमें चुनिंदा प्रखंडों में पशुधन विकास, डेयरी पालन, सुअर पालन, बकरी पालन और मछली पालन के जरिए पशु आधारित प्रोटीन उत्पादन गतिविधियां आरम्भ की जाएंगी।

त्वरित चारा विकास कार्यक्रम

58. दूध के सतत उत्पादन के लिए चारे की पर्याप्त उपलब्धता आवश्यक है। सम्पूर्ण वर्ष चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु प्रौद्योगिकियों के व्यापक संवर्धन के जरिए चारे के उत्पादन में तेजी लाना आवश्यक है। मैं, त्वरित चारा विकास कार्यक्रम के लिए 300 करोड़ रुपए मुहैया कराने का प्रस्ताव करता हूँ जिससे 25,000 गांवों को किसान लाभान्वित होंगे।

59. माननीय सदस्य इस बात के लिए उत्सुक होंगे कि इन नई पहलों को 300 करोड़ रुपए के आवंटन से क्यों शुरू किया जा रहा है। वास्तव में, संख्या 3 मेरी शुभ संख्या है।

राष्ट्रीय सतत कृषि उत्पादन मिशन

60. जहां खाद्यान्नों की बढ़ती मांग की पूर्ति के लिए कृषि उपज को अधिक से अधिक करने की आवश्यकता है, वहीं हमें कृषि

उत्पादकता को दीर्घकाल तक बनाए रखना है। कई कारकों की वजह से मृदा उर्वरता से गिरावट आयी है। फसल के अवशेषों को हटाए जाने और रासायनिक उर्वरकों के अंधाधुंध इस्तेमाल से तथा मिथ्या कीमतों की वजह से मृदा के उपजाऊपन में कमी और जल-प्रदूषण हुआ है।

61. इन मुद्दों के समाधान के लिए, सरकार का जैविक कृषि पद्धतियाँ, आधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ परम्परागत कृषि कार्य जैसे हरी खाद डालना, जैववैज्ञानिक कीट नियंत्रण और खर-पतवार निवारण प्रबंधन को बढ़ावा देने का प्रस्ताव है।

कृषि ऋण

62. अपनी भूमि से सर्वाधिक लाभ प्राप्ति के लिए, किसानों को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता है। विगत कुछ वर्षों में बैंक कृषि ऋण प्रवाह के लिए निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति निरंतर करते रहे हैं। मैं, किसानों को इस वर्ष के 3,75,000 करोड़ रुपये के ऋण के लक्ष्य को बढ़ाकर 2011-12 में 4,75,000 करोड़ रुपये कर रहा हूँ। बैंकों से कहा गया है कि कृषि के लिए सीधा उधार और छोटे और सीमांत किसानों को ऋण प्रदान करने की गति में तेजी लाएं।

63. किसानों को 7 प्रतिशत की ब्याज की दर से अल्पावधिक फसल ऋण प्रदान करने की मौजूदा ब्याज आर्थिक सहायता योजना 2011-12 के दौरान जारी रहेगी। पिछले बजट में, मैंने उन किसानों को अतिरिक्त 2 प्रतिशत की ब्याज सहायता प्रदान की थी, जिन्होंने अपनी फसल ऋण की वापसी समय पर की थी। इस योजना की प्रतिक्रिया अच्छी रही। इन किसानों को और प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए, मैं, 2011-12 में 3 प्रतिशत की अतिरिक्त सहायता देने का प्रस्ताव करता हूँ। इस प्रकार, ऐसे किसानों के लिए प्रभावी ब्याज दर 4 प्रतिशत प्रतिवर्ष होगी।

64. कृषि ऋण के प्रवाह हेतु वर्धित लक्ष्य को देखते हुए, मैं सरकार की इक्विटी के रूप में धरणाबद्ध तरीके से 3,000 करोड़ रुपये लगा कर नाबार्ड के पूँजी आधार को मजबूत करने का प्रस्ताव करता हूँ। इससे इसकी प्रदत्त पूँजी बढ़कर 5,000 करोड़ रुपये हो जाएगी। नाबार्ड सहकारी ऋण संस्थाओं और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अल्पावधिक फसल ऋणों को रियायती दरों पर पुनर्वित्त पोषण कर सके, इसके हेतु, मैं अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र उधार की कमी से 2011-12 के लिए नाबार्ड की अल्पावधिक ग्रामीण ऋण निधि में 10,000 करोड़ रुपये का अंशदान करने का प्रस्ताव करता हूँ।

मेगा फूड पार्क

65. सब्जियों और फलों के बढ़ते उत्पादन के बावजूद इनकी उपलब्धता खुदरा क्षेत्र में कई अड़चनों की वजह से अपर्याप्त है। भारत में फल और सब्जी उत्पादन का लगभग 40 प्रतिशत भाग भंडारण कोल्ड स्टोरेज और परिवहन अवसंरचना की कमी के कारण बर्बाद हो जाता है। इन मुद्दों के समाधान के लिए ग्यारहवीं योजना

में 30 मेगा फूड पार्कों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया था। अब तक, 15 ऐसे पार्कों को मंजूरी दी गई है। 2011-12 में 15 और मेगा फूड पार्कों की स्थापना के लिए अनुमोदन प्रदान किया जा रहा है।

भंडारण क्षमता और कोल्ड स्टोरेज शृंखलाएं

66. 2008 से 2010 के वर्षों में खाद्यान्न अधिप्राप्ति के अत्यधिक उच्च स्तर देखे गए। 1 जनवरी, 2011 को, केन्द्रीय पूल में खाद्यान्न भंडार 470 लाख मीट्रिक टन हो गया था जो 1 जनवरी 2007 के 174 लाख मीट्रिक टन की अपेक्षा में 2.7 गुणा अधिक है। इतनी बढ़ी मात्रा को रखने के लिए, भंडार क्षमता बढ़ाये जाने की आवश्यकता है। निजी उद्यमियों और भंडारण निगमों के जरिए 150 लाख मीट्रिक टन की नई भंडारण क्षमता के सृजन की प्रक्रिया को तेज कर दिया गया है। लोक उद्यमी गारंटी (पेग) योजना के तहत, आधुनिक खत्तियों (साइलों) के जरिए, 20 लाख मीट्रिक टन की भंडारण क्षमता सृजित करने का निर्णय लिया गया है। जहाँ हम मार्च, 2011 तक मौजूदा मंजूरी के आधार पर लगभग 2.6 लाख टन की क्षमता बढ़ा लेंगे, वहाँ मार्च, 2012 तक अतिरिक्त क्षमता बढ़कर 40 लाख टन की हो जाएगी। वर्ष 2011-12 के दौरान, ग्रामीण गोदाम योजना के तहत, अन्य 24 लाख मीट्रिक टन की भंडारण क्षमता का सृजन कर लिया गया है।

67. कोल्ड स्टोरेज परियोजनाओं में निवेश तेजी से पकड़ रहा है। इस वर्ष 1.4 लाख मीट्रिक टन की क्षमता वाली 24 कोल्ड स्टोरेज परियोजनाओं को राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत मंजूरी दी गई है। इसके अतिरिक्त, 5 लाख मीट्रिक टन से अधिक की क्षमता की 107 कोल्ड स्टोरेज परियोजनाओं को राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है।

68. अब से इस क्षेत्र में निवेश जुटाने के लिए, आधुनिक भंडारण क्षमता के सृजन में पूँजी निवेश वित्त मंत्रालय की व्यवहार्यता अंतराल वित्त पोषण योजना के लिए उपर्युक्त होगा। कोल्ड स्टोरेज शृंखलाओं और फसल पश्च भंडारण को अवसंरचना उप-क्षेत्र के रूप में मान्यता प्रदान करने का भी प्रस्ताव है।

कृषि उपज-विपणन अधिनियम

69. सब्जियों और फलों में मुद्रास्फीति की हाल की घटना ने हमारी आपूर्ति शृंखलाओं में गंभीर खामियां उजागर की हैं। सरकारी विनियमित मंडियां कभी-कभी खुदरा विक्रेताओं को उनके उद्यमों के खाद्य किसानों को एकीकृत होने से रोकती हैं। राज्य सरकारों के लिए कृषि उपज विपणन अधिनियम की समीक्षा करने और फिर से बने अधिनियम को लागू करने की आवश्यकता है।

अवसंरचना और उद्योग

70. हमारे विकास की गति में सुधार लाने में अवसंरचना का स्थान महत्वपूर्ण है। वर्ष 2011-12 के लिए, अवसंरचना क्षेत्र हेतु 2,14,000 करोड़ रुपये से अधिक के आवंटन का प्रस्ताव है, जो चालू वर्ष के आवंटन की अपेक्षा 23.3 प्रतिशत अधिक है। यह सकल बजटीय सहायता व्यय का 48.5 प्रतिशत है।

71. देश में सार्वजनिक क्षेत्र की आस्तियों के निर्माण हेतु सरकारी निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के साथ हमारा अनुभव काफी अच्छा रहा है। सरकारी निजी भागीदारी वाली परियोजनाओं की पहचान करने, परिकल्पना तैयार करने, ढांचा तैयार करने और प्रबंधन में लोक पदाधिकारियों की क्षमताएं बढ़ाने हेतु राष्ट्रीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम आरम्भ किया है। हमारा यह प्रयास है कि हम एक समेकित नीति तैयार करें जिनका उपयोग केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा सरकारी निजी भागीदारियों के और विकास में किया जा सके।

72. अवसंरचना परियोजनाओं को दीर्घावधिक वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सरकार ने भारत अवसंरचना वित्त कम्पनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) की स्थापना की है। 31 मार्च, 2011 तक 20,000 करोड़ रुपए और 31 मार्च, 2012 तक 25,000 करोड़ रुपए का संचयी संवितरण लक्ष्य प्राप्त करने की आशा है। बजट 2009-10 में घोषित वित्तपोषण प्राप्त करने की योजना कार्यान्वित कर दी गई है और सात परियोजनाओं को 1500 करोड़ रुपए के ऋण से मंजूरी दी गई है। 2011-12 के दौरान 5,000 करोड़ रुपए की एक अन्य परियोजना को मंजूरी दे दी जाएगी।

73. रेल, पत्तनों, आवास और राजमार्ग विकास में अवसंरचना विकास को बढ़ावा देने की दृष्टि से, मैं वर्ष 2011-12 में विभिन्न सरकारी उपक्रमों द्वारा जारी किए जाने वाले 30,000 करोड़ रुपए के कर मुक्त बांडों की अनुमति देने का प्रस्ताव करता हूँ। इसमें भारतीय रेल वित्त निगम द्वारा 10,000 करोड़ रुपए, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के 10,000 करोड़ रुपए, हुडको के 5,000 करोड़ रुपए तथा पत्तनों के 5,000 करोड़ रुपए के बांड शामिल हैं।

74. अवसंरचना वित्तपोषण के लिए विदेशी निधियां जुटाने हेतु, मैं अधिसूचित अवसंरचना ऋण निधियों के रूप में विशेष साधना सृजित करने का प्रस्ताव करता हूँ। मैं अपने भाषण के भाग-ख में इस पर चर्चा करूंगा।

राष्ट्रीय विनिर्माण नीति

75. सकल घरेलू उत्पाद की अनवरत वृद्धि और युवा पीढ़ी के लिए उत्पादक रोजगार हेतु, यह आवश्यक है कि विनिर्माण क्षेत्र में विकास बढ़े। हम उम्मीद करते हैं कि दस वर्षों की अवधि के सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण की हिस्सेदारी 16 प्रतिशत से बढ़कर 25 प्रतिशत हो जाएगी। सरकार विनिर्माण नीति लाएगी जो कि स्व-विनियमन के जरिए अनुपालन भार में कमी लाएगी और भारतीय उद्योगों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक बनाने में सहायक होगी।

76. प्राकृतिक संसाधन की प्रापण नीति एवं आवंटन, कीमत निर्धारण एवं उपयोग में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने दो समितियां गठित की हैं। इनकी सिफारिशें तीन महीनों में मिल जाएंगी।

77. अवसंरचना और खनन से जुड़े विभागों सहित विविध विभागीय गतिविधियों से उत्पन्न पर्यावरण सम्बन्धी चिंताओं के समाधान से संबंधित सभी विषयों पर विचार-विमर्श करने हेतु, एक मंत्रिदल गठित किया गया है। यह दल मौजूदा संविधियों नियमों, विनियमनों

और दिशा-निर्देशों में बदलावों का सुझाव देगा और अपनी सिफारिशें समय-बद्ध रूप से प्रस्तुत करेगा।

78. भारतीय आटोमोबाइल बाजार विश्व में दूसरा सबसे तेजी से उभरता हुआ बाजार है और इसने इस वर्ष लगभग 30 प्रतिवर्ष की वृद्धि दर दर्शायी। पूरे विश्व में, हाइब्रिड तथा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के क्षेत्र में भारी निवेश हो रहे हैं। स्वच्छ और साफ सार्वजनिक परिवहन मुहैया कराने के लिए, सभी पण्यधारकों के सहयोग से नेशनल हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल मिशन शुरू किया जाएगा।

79. जेएनएनयूआरएम के तहत 15,260 आधुनिक लो-फ्लोर तथा सेमी-लो फ्लोर बसों के वित्तपोषण, नये यात्रियों की आरामदेही के साथ-साथ पूरे भारत में शहरी परिवहन की तस्वीर बदल दी है। वर्ष 2011-12 में, दिल्ली मेट्रो का चरण-III तथा मुम्बई मेट्रो की लाइन-III को शुरू करने का प्रस्ताव है। बंगलुरु, कोलकाता तथा चेन्नई की चल रही मेट्रो परियोजनाओं के शीघ्र क्रियान्वयन के लिए वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाएगी।

80. उर्वरक क्षेत्र में निवेश, पूंजी प्रधान होता है और अधिक जोखिम भरा माना जाता है। उर्वरक उत्पादन में अवसंरचनागत उप-क्षेत्र के रूप में पूंजी निवेश को शामिल करने का प्रस्ताव है।

निर्यात

81. हमारी निर्यात प्रक्रियाओं की कार्यक्षमता में सुधार को चिह्नित करने और उसे प्राप्त करने के उपाय सुझाने के लिए वाणिज्य विभाग द्वारा गठित लेनदेन लागत संबंधी कार्यबल ने अपना कार्य पूरा कर लिया है। कार्यबल द्वारा दिए गए इक्कीस सुझाव क्रियान्वित किए जा चुके हैं। शेष दो पर कार्यवाई अगले दो महीनों में की जाएगी। इससे लेनदेन लागत में लगभग 2,100 करोड़ रुपए की कमी आएगी।

82. सीमा-शुल्क प्राधिकारियों द्वारा कार्गो की शीघ्र निकासी करने तथा सीमा-शुल्क प्रशासन के आधुनिकीकरण के लिए मैं सीमा-शुल्क में स्व-निर्धारण की शुरुआत करने का प्रस्ताव करता हूँ। इसके तहत, आयातक और निर्यातक ईडीआई प्रणाली में अपनी घोषणाओं को प्रस्तुत करते समय अपनी शुल्क संबंधी देयताओं का स्वयं निर्धारण करेंगे। विभाग एक चुनिंदा प्रणाली प्रेरक आधार पर ऐसे निर्धारणों का सत्यापन करेगा।

83. वस्तुओं के निर्यात के लिए प्रयुक्त सेवाओं पर प्रदत्त कर से संबंधित वापसियों की मंजूरी में बहुत कठिनाइयां आती रही हैं। मैं, एक अधिक सरलीकृत तथा शीघ्र तरीके से शुल्क वापसी की तर्ज पर इन करों की वापसी हेतु जल्दी ही एक स्कीम शुरू करने का प्रस्ताव करता हूँ। एक नई स्कीम भी शुरू की जा रही है जिसमें विशेष आर्थिक जोन (सेज) में कार्यरत इकाइयां जोन के भीतर पूरी तरह उपभोग में लाई गई सेवाओं की कर-मुक्त रसीद तथा उनकी वापसियां आसान तरीके से प्राप्त कर सकेंगे।

84. मेगा क्लस्टरों में रोजगार और निर्यात की भारी संभावना है। मैं, चमड़े के उत्पादों के विकास के लिए यह मेगा क्लस्टर स्कीम लागू करने का प्रस्ताव करता हूँ। 2011-12 में सात मेगा लेदर क्लस्टर स्थापित किए जाएंगे। मैं, हस्तशिल्प मेगा क्लस्टर के विकास हेतु जोधपुर को शामिल किए जाने का भी प्रस्ताव करता हूँ।

कार्य धन

85. काला धन बनाना और उसका इस्तेमाल करना गंभीर चिंता का विषय है। इस समस्या से कारगर तरीके से निपटने के लिए, सरकार ने एक पांच सूत्री कार्ययोजना लागू की है जिसमें शामिल हैं— काले धन के विरुद्ध वैश्विक लड़ाई में साथ देना; उपयुक्त कानूनी ढांचा तैयार करना; अनुचित तरीकों से अर्जित निधियों से निपटने के लिए अस्थायी स्थापित करना; क्रियान्वयन के लिए प्रणालियाँ विकसित करना; और प्रभावशाली कार्रवाई के लिए जनशक्ति को कौशल का प्रशिक्षण देना।

86. हमने पिछले वर्ष जून में वित्तीय कृतिक कार्यबल (एफएटीएफ) की सदस्यता ली थी। यह धन-शोधन प्रतिषेध हेतु जी-20 की एक महत्वपूर्ण पहल है। हम वित्तीय ईमानदारी तथा आर्थिक विकास संबंधी कार्यबल, यूरोपियन समूह (ईएजी) तथा कर प्रयोजनार्थ पारदर्शिता एवं सूचना के आदान-प्रदान संबंधी वैश्विक फोरम में भी शामिल हुए हैं।

87. इस वर्ष हमने 10 मौजूदा दोहरे कराधान परिवर्जन करारों के प्रावधानों के संशोधन सहित 11 कर सूचना आदान-प्रदान करार (टीआईईए) और 13 नए दोहरे कराधान परिवर्जन करारों (टीडाए) पर विचार विमर्श किया है। कर सूचना के आदान-प्रदान तथा मूल्य निर्धारण अंतरण सम्बन्धी मामलों पर प्रभावी ढंग से निपटने के लिए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के विदेशी कर प्रभाग को सुदृढ़ किया गया है। इस मामले पर कार्य करने के लिए सूचना के आदान-प्रदान हेतु, एक समर्पित प्रकोष्ठ स्थापित किया जा रहा है।

88. हमारे धन शोधन विधान में 2009 में संशोधन ने इसके अधिकार-क्षेत्र तथा अनुप्रयोग में बहुत अधिक वृद्धि कर दी है। इस विधान के तहत वर्ष 2005 से 2008 तक दर्ज मामलों की संख्या 50 थी, जो इस वर्ष के जनवरी माह तक बढ़कर 1200 तक जा पहुँची है। बढ़े हुए कार्यभार से बखूबी निबटने के लिए प्रवर्तन निदेशालय की कर्मचारी संख्या बढ़ाकर तीन गुनी कर दी गयी है।

89. वित्त मंत्रालय द्वारा बेहिसाबी आय और देश के बाहर एवं देश में रखे गए धन के संबंध में एक अध्ययन शुरू किया गया है। यह इस धन पर कर लगाने एवं इस धन को देश में वापस लाने के लिए तैयारी सुझावेगा।

90. व्यापक और अधिकृत अवैध व्यापार भी काले धन का एक प्रमुख बड़ा जरिफ है। इस अवैध व्यापार और मनोचिकित्सीय पदार्थों के विपणन निवर्तनों को कठोर बनाने के लिए, मैं निकट भविष्य में व्यापक राष्ट्रीय नीति घोषित करने का प्रस्ताव करता हूँ।

III. समावेशी सुदृढ़ीकरण

91. संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने समावेशी विकास पर ध्यान देते हुए राजकीय नीति में प्रमुख दिशापरक परिवर्तन किया है। क्योंकि, के काम के अधिकार के लिए विभिन्न हकदारियों के सृजन से हमारे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में समृद्धि, रोजगार और उर्जास्वता को बढ़ावा मिलेगा। सूचना के अधिकार और शिक्षा का अधिकार सशक्तीकरण के व प्रभावशाली हाथपाए हैं जिनसे हमारे वह

सामाजिक असन्तुलन अवश्य दूर होंगे। देश ने भूख और कुपोषण को बहुत झेला है। राज्य सरकारों सहित सभी पण्यधारकों के साथ व्यापक परामर्श के बाद, हम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक (एनएफएसबी) को अंतिम रूप देने वाले हैं। इसे इस वर्ष शीघ्र ही संसद में पेश किया जाएगा। 2011-12 में सामाजिक क्षेत्र में 1,60,887 करोड़ रुपये के आबंटन का प्रस्ताव है जो पिछले वर्ष में 17 फीसदी अधिक है, यह कुल आयोजना आबंटन का 36.4 प्रतिशत बैठता है।

भारत निर्माण

92. संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के फ्लैगशिप योजनाएं समावेशी विकास के इसके एजेंडे को लागू कराने के मुख्य साधन रही हैं। भारत निर्माण के प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई), त्वरित सिंचाई सुविधा कार्यक्रम, राजीव गांधी ग्रामी./विद्युतीकरण योजना, इंदिरा आवास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम तथा ग्रामीण टेलीफोनी सम्मिलित हैं। वर्ष 2011-12 के लिए भारत निर्माण को कुल मिलाकर, 58,000 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं। यह मौजूदा वर्ष से 10,000 करोड़ रुपये अधिक है। देश में सभी 2,50,000 पंचायतों को तीन वर्ष में ग्रामीण ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी मुहैया कराने के लिए एक योजना को अंतिम रूप दिया गया है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीनरेगा)

93. 100 रुपये की वास्तविक दैनिक मजदूरी दिलाने के बारे में पिछली बजट घोषणा के अनुसरण में सरकार ने एमजीनरेगा के तहत कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को अधिसूचित करने का निर्णय लिया है। इससे 14 जनवरी, 2011 को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मजदूरी बढ़ गई है। इसके चलते देश भर में फ़ैले लाभार्थियों की मजदूरी में वृद्धि हुई है।

94. आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायक एकीकृत बाल विकास सेवा स्कीम की रीढ़ हैं। मैं प्रसन्नतापूर्वक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तथा आंगनवाड़ी सहायकों का मेहनताना बढ़ाकर क्रमशः 1,500 रुपये से 3,000 रुपये तथा 750 रुपये से 1,500 रुपये प्रतिमाह करने की घोषणा करता हूँ। यह 1 अप्रैल, 2011 से लागू होगा। पूरे देश में करीब 22 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तथा सहायक इस वृद्धि से लाभान्वित होंगे।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातीय उपयोजना

95. बजट 2011-12 में, पहली बार अनुसूचित जाति उपयोजना तथा अनुसूचित जनजातीय उप-योजना के लिए विशिष्ट आबंटन निर्धारित किए जा रहे हैं। इन्हें संगत मंत्रालयों तथा विभागों के बजट में पृथक लघु लेखा शीर्षों के अन्तर्गत अलग से दर्शाया जाएगा। इसके अलावा, मैं जनजातीय वर्गों के लिए 2010-11 में किए गए 185 करोड़ रुपये के बजट आबंटन को बढ़ाकर 2011-12 में 244 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव करता हूँ।

शिक्षा

96. विकसित देशों की तुलना में अपेक्षाकृत युवा आबादी का हमारा "जनसांख्यिकी लाभार्थ" चुनौती से कहीं बढ़कर एक अवसर है। 2025 में 70 प्रतिशत से अधिक भारतीय काम काजी आयु के

होंगे। इस संदर्भ में, माध्यमिक शिक्षा सभी के लिए सुलभ बनाने, उच्चतर शिक्षा क्षेत्र में हमारे विद्वानों की प्रतिशतता को बढ़ाने और कौशल प्रशिक्षण की व्यवस्था करना अत्यावश्यक है। मैं शिक्षा के लिए 52.057 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव करता हूँ जो मौजूदा वर्ष की तुलना में 24 प्रतिशत अधिक है।

सर्वशिक्षा अभियान

97. बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार को लागू करने के लिए सर्वशिक्षा अभियान के मौजूदा संवाहन संबंधी मानकों को संशोधित किया गया है। यह 1 अप्रैल, 2010 से लागू है। वर्ष 2011-12 के लिए, मैं, 21,000 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव रखता हूँ। यह 2010-11 के बजट में किए गए 15,000 करोड़ रुपये के आवंटन से 40 प्रतिशत अधिक है। 'माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायिकरण' नामक एक संशोधित केन्द्र प्रायोजित योजना हमारे युवाओं में रोजगार की स्थिति में सुधार हेतु 2011-12 से कार्यान्वित की जाएगी।

98. सशक्तीकरण शिक्षा से जन्म लेता है। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने जहाँ मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों की पहुँच को भी सुगम बनाया है, वहीं अभी तक मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति स्कीम में अभाव सा चल रहा था। वर्ष 2011-12 में, मैं, नौवी तथा दसवीं कक्षा में पढ़ रहे अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के जरूरतमंद विद्यार्थियों के लिए एक छात्रवृत्ति स्कीम शुरू करने का प्रस्ताव करता हूँ। इससे अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के तकरीबन 40 लाख विद्यार्थी लाभान्वित होंगे।

राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क

99. मार्च 2010 में अनुमोदित राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क (एन.के.एन.) ऑप्टिकल फाइबर आधार रेखा के जरिए 1500 उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान संस्थान को जोड़ेगा। मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान 190 संस्थानों को राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। चूँकि आधार मार्च, 2011 तक तैयार होगा, अतः सभी 1500 संस्थानों को मार्च 2012 तक कनेक्टिविटी मुहैया कराई जा सकेगी।

नवाचार

100. अनुसंधान एवं विकास के औपचारिक प्रतिमान से बाहर निकलने के लिए, भारत में नवाचारों के सूत्रपात के लिए एक रूपरेखा तैयार करने की दृष्टि से श्री सैम पित्रोदा के नेतृत्व में एक राष्ट्रीय नवाचार परिषद गठित की गई है। इसी की तर्ज पर प्रत्येक राज्य में राज्य नवाचार परिषदें तथा केन्द्रीय मंत्रालयों से सम्बद्ध क्षेत्रीय नवाचार परिषदों के गठन की प्रक्रिया जारी है।

101. विश्वविद्यालयों तथा अकादमिक संस्थाओं में उत्कृष्टता को स्वीकार करने हेतु सरकार विशेष अनुदान मुहैया कराती रही है। 2011-12 के लिए, मैं निम्नलिखित के लिए व्यवस्था करने का प्रस्ताव करता हूँ:

- प. बंगाल में मुर्शिदाबाद तथा केरल में मल्लापूरम में स्थित किए जाने वाले अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय के प्रत्येक भावी केंद्र को 50 करोड़ रुपये;

- पुकौड, केरल में केरल पशुचिकित्सालय और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय को 100 करोड़ रुपये का एक मुश्त अनुदान;
- महात्मा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा के कोलकाता तथा इलाहाबाद में केंद्रों की स्थापना हेतु प्रत्येक के लिए 10 करोड़ रुपये;
- एकबारागी अनुदान के रूप में आई.आई.टी., खड़गपुर को 200 करोड़ रुपये;
- राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास केंद्र, श्रीपेरुम्बुदुर, तमिलनाडु के लिए 20 करोड़ रुपये;
- आईआईएम, कोलकाता को उनकी वित्तीय अनुसंधान एवं व्यापार प्रयोगशाला की स्थापना में सहायता हेतु 20 करोड़ रुपये;
- मौलाना आज़ाद शिक्षा प्रतिष्ठान के लिए 200 करोड़ रुपये;
- सेंटर फॉर डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स एण्ड रतन टाटा लाइब्रेरी, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, दिल्ली के लिए 10 करोड़ रुपये; और
- मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के लिए 10 करोड़ रुपये।

कौशल विकास

102. मुझे सदन को यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद (एनएसडीसी) 15 करोड़ कुशल श्रमिकों के सृजन सम्बन्धी अपना अधिशेष नियत लक्ष्य वर्ष, 2022 से दो वर्ष पहले प्राप्त करने की राह पर अग्रसर है। यह कुल 658 करोड़ रुपये के वित्तपोषण से 26 परियोजनाओं को पहले ही स्वीकृत कर चुका है। यह उम्मीद है कि इन परियोजनाओं से ही अगले दस वर्षों में 4 करोड़ से अधिक कुशल श्रमिक तैयार कर दिए जाएंगे। चालू वर्ष में, 20,000 व्यक्तियों को कौशल प्रशिक्षण दिलाया गया है। इनमें से, 75 प्रतिशत रोजगार प्राप्त कर चुके हैं। अगले वर्ष, मैं राष्ट्रीय कौशल विकास निधि को अतिरिक्त 500 करोड़ रुपये मुहैया कराऊंगा।

103. गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर की 150वीं जयन्ती मनाने के राष्ट्रीय समारोह 7 मई, 2011 से नई दिल्ली में शुरू होंगे। यूरोप, अमरीका और एशिया के कई देशों में महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किए जायेंगे। भारत-बांग्लादेश समारोह समिति के संयुक्त तत्वावधान में अनेक उत्सव आयोजित किए जाने का प्रस्ताव है। गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर की स्मृति में विश्व-बन्धुत्व के मूल्यां के संवर्धन के लिए 1 करोड़ रुपये का अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी स्थापित किया जा रहा है।

स्वास्थ्य

104. स्वास्थ्य के संबंध में, मैं 2011-12 में आयोजना व्यय को 20 प्रतिशत तक बढ़ाकर 26,760 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव करता हूँ। गरीब और सीमान्त मजदूरों को प्राथमिक स्वास्थ्य बीमा रक्षा आवरण मुहैया कराने के लिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना एक कारगर साधन बनकर उभरी है। अब इसका विस्तार एमजीनरेगा लाभार्थियों, बीड़ी कामगारों तथा अन्य तक किया जा रहा है। वर्ष 2011-12 में, मैं, जोखिम भरे खनन तथा स्लेट और स्लेट पेंसिल,

डोलोमाइट, माइका और एसबेस्टेस आदि सम्बद्ध उद्योगों में काम कर रहे असंगठित क्षेत्र के कामगारों को भी इसके अंतर्गत लाने के लिए इस स्कीम का विस्तार करने का प्रस्ताव करता हूँ।

वित्तीय समावेशन

105. मैंने, अपने पिछले बजट भाषण में बैंकों को मार्च 2012 तक 2000 से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधा मुहैया कराने की सलाह दी थी। बैंकों ने समुचित प्रौद्योगिकी की इस्तेमाल करते हुए बैंकिंग सुविधाएं मुहैया कराने के लिए ऐसी 73,000 बस्तियों को अभिचिह्नित किया है। लोगों को बैंक खाते खोलने के लिए सूचित, शिक्षित व अभिप्रेरित करने हेतु एक मल्टी मीडिया अभियान "स्वाभिमान" शुरू किया गया है। इस वर्ष के दौरान बैंक 20,000 गांवों को इसके अंतर्गत सम्मिलित करेंगे। शेष गांवों को 2011-12 में शामिल कर लिया जाएगा।

असंगठित क्षेत्र

106. मैंने, बजट 2010-11 में, "स्वावलम्बन" नामक एक सह-अंशदायी पेंशन स्कीम की घोषणा की थी। असंगठित क्षेत्र के कामगारों द्वारा इस स्कीम का स्वागत किया गया है। अब तक, 4 लाख से ज्यादा आवेदन मिल चुके हैं। प्राप्त फीडबैक के आधार पर, मैं निकास मानकों में छूट दे रहा हूँ जिसके द्वारा स्वावलम्बन के अंतर्गत किसी भी अंशदाता में 60 वर्ष के बजाय 50 वर्ष, या 20 वर्ष को न्यूनतम अवधि, इनमें से जो भी परवर्ती हो, के बाद निकासी की अनुमति होगी। मैं, वर्ष 2010-11 तथा 2011-12 के दौरान स्वावलम्बन योजना में नामांकित हो चुके सभी अंशधारकों को तीन से पांच वर्षों तक सरकारी अंशदान का फायदा देने का प्रस्ताव करता हूँ। जैसा कि अनुमान है, मार्च, 2012 तक 20 लाख लाभार्थी इस स्कीम में शामिल होंगे।

107. गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रहे लाभार्थियों के लिए मौजूदा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन स्कीम के तहत व्यक्ति अर्हता 65 वर्ष से घटाकर 60 वर्ष करने का प्रस्ताव है। जो 80 वर्ष या इसके अधिक आयु के हैं, उनके लिए पेंशन 200 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये किए जाने का प्रस्ताव है।

पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन

वन

108. वनों का संरक्षण तथा वनरोपण का पारिस्थितिक, आर्थिक और सामाजिक महत्व है। हमारी सरकार ने दस वर्षीय भारत मिशन की एक महत्वाकांक्षी स्कीम शुरू की है। वर्ष 2011-12 में इसका क्रियान्वयन शुरू करने के लिए, मैं, राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि में से 200 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ।

पर्यावरणीय प्रबंधन

109. पर्यावरणीय प्रदूषण देशभर में एक गंभीर लोक स्वास्थ्य संबंधी चिंता के रूप में उभरा है। मैं, पर्यावरणीय सुधार उपाय कार्यक्रमों की शुरुआत करने के लिए 2011-12 में केन्द्र के अंशदान के तौर पर राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि से 200 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ।

नदियों तथा झीलों की सफाई

110. राष्ट्रीय गंगा नदी थाला प्राधिकरण के तहत, 2010-11 में कई परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं। इस रफ्तार को और बढ़ाया जाएगा। सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक महत्व की कई नदियां और झीलें हैं जिनकी सफाई किए जाने की जरूरत है। वर्ष 2011-12 में, मैं, गंगा नदी को छोड़कर, कुछ महत्वपूर्ण झीलों तथा नदियों की सफाई हेतु 200 करोड़ रुपये का विशेष आवंटन करने का प्रस्ताव करता हूँ।

कुछ अन्य पहल

111. पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा विशेष श्रेणी के राज्यों में विकास को बढ़ाने हेतु, 2011-12 के लिए विशेष सहायता का आवंटन लगभग दुगुना करके 8000 करोड़ रुपये किया गया है। इसमें से, 5,400 करोड़ रुपए मुक्त विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में आवंटित किए गए हैं।

112. सरकार ने प्रधानमंत्री की पुनर्निर्माण योजना में जम्मू-कश्मीर को 28,000 करोड़ रुपए की विशेष सहायता दी है। इसके अतिरिक्त, मौजूदा वर्ष में लगभग 8,000 करोड़ रुपए विकासात्मक जरूरतों के लिए दिए गए हैं। राज्य के लद्दाख और जम्मू क्षेत्रों में 24 माह के भीतर समाधान किए जा सकने वाली अवसंरचनात्मक जरूरतों के निर्धारण के लिए बने कार्यदल ने क्रमशः 416 करोड़ रुपए और 497 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजनाओं की सिफारिश की है। मैं, 2011-12 में इन चिह्नित परियोजनाओं हेतु लद्दाख के लिए 100 करोड़ रुपए तथा जम्मू के लिए 150 करोड़ रुपए की व्यवस्था कर रहा हूँ।

113. पिछड़े क्षेत्रों में विकास को गति देने के लिए, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के तहत किए गए 7,300 करोड़ रुपए के आवंटन को 35 प्रतिशत से अधिक तक बढ़ाकर 9,890 करोड़ रुपए कर दिया गया है।

114. वामपंथी अतिवाद से प्रभावित जिलों से जुड़ी समस्याओं के निराकरण के लिए, दिसम्बर, 2010 में 60 चुनिंदा जनजातीय और पिछड़े जिलों के लिए एक एकीकृत कार्य योजना (आईएपी) शुरू की गई थी। यह स्कीम वर्ष 2010-11 और 2011-12 के दौरान क्रमशः 25 करोड़ रुपए और 30 करोड़ रुपए के 100 प्रतिशत एक-मुश्त अनुदान के साथ कार्यान्वित की जा रही है। आवंटित निधियां जिला स्तर की समितियों के नियंत्रण में रखी जाती हैं जो स्थानीय जरूरतों के अनुसार विकास योजनाओं पर खर्च करने के लिए स्वतंत्र हैं।

115. वामपंथी अतिवाद का मुकाबला करने में लगे केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों के जवानों द्वारा दी गई शहादत के सम्मान में, 100 प्रतिशत विकलांगता के लिए 9 लाख रुपए की एकमुश्त अनुग्रह क्षतिपूर्ति अब रक्षा एवं अर्द्ध सैनिक बलों के उन कर्मियों को मंजूर की जाएगी जो सरकारी सेवा में आई अथवा हुई विकलांगता के कारण विकित्सा के आधार पर नौकरी से निवृत्त हो जाते हैं। 20 से 99 प्रतिशत तक विकलांगता वाले कर्मियों को अनुपातिक राशि दी जाएगी।

116. बजट 2011-12 में, रक्षा सेवाओं के लिए 1,64,415 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गयी है जिसमें पूंजीगत व्यय के लिए 69,199 करोड़ रुपए शामिल हैं। कहने की आवश्यकता नहीं कि देश की रक्षा के लिए किसी भी आवश्यकता को पूरा किया जाएगा।

117. न्याय देने में शीघ्रता लाने के लिए, न्याय विभाग के 2011-12 के आयोजना प्रावधान में तौगुनी वृद्धि करके इसे 1,000 करोड़ रुपये किया गया है। इस बड़े हुए प्रावधान से कानूनी अवसंरचना निर्माण तथा ई-न्यायालय संबंधी परियोजना निर्माण कार्य में मदद मिलेगी।

जनगणना 2011

118. देश में 15वीं जनगणना 9 फरवरी से आरंभ हो गयी है। यह देश में सबसे बड़ी प्रशासनिक कवायद है जिससे जनसंख्या के विभिन्न समाजिक-आर्थिक मापदंड संबंधी सांख्यिकीय आंकड़े प्राप्त होते हैं।

119. जनगणना 2011 में, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों को छोड़कर, जातियों की गणना करने की जबरदस्त मांग की अनुक्रिया में यह निर्णय लिया गया है कि 'जाति' की गणना के लिए एक पृथक समयबद्ध कवायद की जाएगी। यह जून 2011 में शुरू होगी और 30 सितम्बर, 2011 तक पूरी हो जाएगी।

IV. शासन में सुधार

अब मैं शासन में सुधार हेतु किए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण उपायों की तरफ आता हूँ।

यूआईडी मिशन

120. यूआईडी मिशन की शुरुआत हो चुकी है तथा बड़ी संख्या में आधार नंबर सृजित किए जा रहे हैं। अब तक, 20 लाख आधार नंबर दिए गए हैं और 1 अक्टूबर, 2011 से प्रतिदिन 10 लाख नंबर सृजित किए जाएंगे। विभिन्न स्कीमों के अभिशासन में सेवा सुपुर्दगी, जवाबदेही एवं पारदर्शिता के लिए आधार की क्षमता प्राप्त करने के लिए अब रास्ता तैयार है।

सूचना प्रौद्योगिकी की पहल

121. एक कारगर कर प्रशासन का आधार एक मजबूत आईटी अवसंरचना और वर्धित करदाता सेवाओं के लिए उसका विस्तार किया जाना होता है। मुझे इस सम्माननीय सदन को यह बताने हुए खुशी हो रही है कि इस उद्देश्य के लिए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क बोर्ड (सीबीईसी), दोनों ने निम्नलिखित उपाय किए हैं :

- आयकर विवरणी ऑन-लाइन पर तैयार और प्रस्तुत करना, 32 एजेंसी बैंकों के माध्यम से करों का ई-भुगतान, करदाताओं के बैंक खातों में सीधे (धन) वापसी के इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन और टीडीएस विवरणियां इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत करने हेतु ईसीएस सुविधा अब देशभर में उपलब्ध है। इन उपायों से करदाता आयकर कार्यालय में जाए बिना, अपनी कर संबंधी जिम्मेदारियां पूरा करने में समर्थ हुए हैं।
- बेंगलुरु स्थित केंद्रीकृत प्रोसेसिंग सेंटर (सीपीसी) ने 2010-11 में अपनी दैनिक प्रोसेसिंग क्षमता 20,000 विवरणियों से बढ़ाकर 1.5 लाख विवरणियां कर दी हैं। इस परियोजना ने 2011 में ई-गवर्नेंस के लिए स्वर्ण पुरस्कार जीता है। मई 2011 तक और दो सीपीसी मानेसर और पुणे में कार्य करना शुरू कर देंगे तथा चौथा सीपीसी 2011-12 में कोलकाता में स्थापित किया जाएगा।

- सीबीईसी, अपनी आईटी समेकन परियोजना पूरी हो जाने से, अब अपने मुख्य अनुप्रयोग केन्द्रीय रूप से सीमा-शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तथा सेवा कर में व्यवस्थित कर सकता है। सीमा-शुल्क की ईडीआई प्रणाली अब देशभर में 92 स्थानों में काम कर रही है। सीबीईसी के ई-कॉमर्स पोर्टल 'आईसगेट' को भी ई-गवर्नेंस के लिए स्वर्ण पुरस्कार प्रदान किया गया है।

- दोनों बोर्डों द्वारा 'सेवोत्तम' की संकल्पना अपनाई गई है। सीबीडीटी के तहत आयकर सेवा केंद्रों की तीन प्रायोगिक परियोजनाओं ने लम्बा रास्ता तय किया है। सीबीडीटी इस वर्ष और आठ ऐसे केंद्र चालू करेगा। 2011-12 में देशभर में 50 आयकर सेवा केंद्र स्थापित किए जाएंगे। सीबीईसी ने भी इसी प्रकार के उपाय किए हैं और उनकी प्रायोगिक परियोजनाओं में से चार शुरू हो गई हैं।

- छोट कर कर कर्मी (सीडीपी) विवरणों का इलेक्ट्रॉनिक प्रस्तुतिकरण मजबूत प्रणाली पर हुआ है। बोर्ड शीघ्र ही उन क्षेत्रभागी करदाताओं को अपनी अभिलेखि करेगा जिन्हें आय का विवरण प्रस्तुत करना जरूरी नहीं होगा क्योंकि उनकी कर संबंधी सेवा का निर्वाह उनके नियोक्ता द्वारा छोट पर कर्मी के माध्यम से किया जा चुका है।

- सीबीडीटी करदाताओं के फायदेर विभाग के साथ सीधा संपर्क स्थापित करने के लिए एक प्रत्यक्ष वेब-आधारित सुविधा मुहैया कराएगा जहाँ करदाता अपनी वापसी राशि और पूर्व प्रदत्त करों के बकाया के संबंध में शिकायत दर्ज कर सकें तथा उनके निराकरण की स्थिति पता कर सकें।

122. मैंने अपने पिछले बजट में, राज्यों में वाणिज्यिक करों के कम्प्यूटीकरण के लिए मिशन मोड परियोजनाओं की घोषणा की थी। इनसे राज्य वस्तु एवं सेवा का को शुरू कर सकेंगे। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त 31 परियोजनाओं हेतु निधियां जारी की गई हैं। अधिकांश राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने डीलियों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक भुगतान किए जाने की सुविधा मुहैया कराई है। कई राज्यों ने इलेक्ट्रॉनिक कर विवरणी स्वीकार करना और राज्य व्यापार के लिए अपेक्षित फॉर्म जारी करना शुरू कर दिया है।

123. अर्थव्यवस्था के विकास के चलते, पिछले ज्यों से भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के उपबंधों की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। मैं इस अधिनियम में संशोधन के लिए जल्द की एक विधेयक ला रहा हूँ।

124. पांच वर्ष पहले, हमने देश में एक आधुनिक और जनता के अनुकूल ई-स्टाम्पिंग सुविधा शुरू करने की पहल की थी। अब तक, केवल 6 राज्यों ने ही इस प्रणाली की शुरुआत की है। मैं, राज्यों को उनके वस्तु और भूजीकरण प्रशासन के आधुनिकीकरण तथा अपने तीन वर्षों में जारी किए गए ई-स्टाम्पिंग पहलवान के लिए सहायता देने हेतु 300 करोड़ रुपये के परिव्यय से नई स्कीम आरंभ करने का प्रस्ताव करता हूँ।

125. मैं, ऐसे छोटे करदाताओं, जो संभावित कराधान के कार्यक्षेत्र में आते हैं का अनुपालन भार कम करने के लिए एक नया सरलीकृत विवरणी प्रपत्र 'सुगम' की शुरुआत का प्रस्ताव करता हूँ।

126. समझौता आयोगों द्वारा स्वीकृत किए गए मामलों के कार्यक्षेत्र में बढ़ोतरी से, कई करदाताओं को राहत मिली है। इससे इस आयोग के कार्यभार में भी वृद्धि हुई है। मामलों के शीघ्र निपटान के लिए, इस आयोग की और तीन पीठ स्थापित की जा रही हैं।

127. प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों, दोनों में राजस्व की अच्छी खासी राशि विभिन्न स्तरों पर अपीलों में फंसी रहती है। दोनों बोर्ड भी अपने कर्मचारियों के साथ मुकदमंबाजी में बहुत अधिक प्रयास करते हैं और धन लगाते हैं। राष्ट्रीय वाद नीति को ध्यान में रखते हुए मुकदमों में कमी लाने तथा उच्च राजस्व वाले मामलों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 2010-11 में अनेक कदम उठाए गए हैं। कर प्रभावों की सीमा बढ़ाने के अनुरोध जारी किए गए हैं। उक्त सीमा से कम कर वाले विवाद सरकार द्वारा उच्चतर अपील न्यायालयों में नहीं ले जाए जाएंगे। इन उपायों से राजस्व जुटाने में लगाए गए संसाधनों की उत्पादकता में वृद्धि होगी।

भ्रष्टाचार

128. भ्रष्टाचार से निपटने के उपायों पर विचार करने के लिए, एक मंत्री समूह गठित किया गया है। इस समूह को चुनाव में सरकारी धन लगाने, लोक सेवकों के भ्रष्टाचार के मामलों पर शीघ्र कार्रवाई करने, सरकारी अधिप्राप्ति तथा ठेकों में पारदर्शिता, केंद्रीय मंत्रियों की विवेकाधीन शक्तियों तथा प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के लिए प्रतिस्पर्धी प्रणाली से संबंधित मुद्दों के समाधान का कार्य सौंपा गया है। यह समूह समयबद्ध तरीके से अपनी सिफारिशें देगा।

निष्पादन मॉनीटरिंग और मूल्यांकन प्रणाली

129. दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में, सरकार ने सरकारी विभागों की उनके अधिदेशित कार्यों के संबंध में कार्यक्षमता के मूल्यांकन के लिए एक निष्पादन मॉनीटरिंग मूल्यांकन प्रणाली (पीएमईएस) स्थापित की है। इसमें प्रत्येक विभाग द्वारा एक रिजल्ट फ्रेमवर्क दस्तावेज तैयार करना शामिल है जिसमें वित्त वर्ष के लिए इसके उद्देश्यों तथा प्राथमिकताओं एवं वर्ष की समाप्ति पर पूर्व निर्धारित लक्ष्यों के मुकाबले हासिल उपलब्धियों को रेखांकित किया जाएगा। यह दस्तावेज जनता के सूचनार्थ विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। प्रथम चरण में इस प्रणाली (पीएमईएस) के अंतर्गत 62 विभागों को शामिल किया गया है।

टैग

130. मैंने, 2010-11 के बजट में की गई घोषणा के अनुसरण में एक टेक्नोलॉजी एडवाइजरी ग्रुप फॉर यूनिट प्रोजेक्ट्स (टैगप) का गठन किया था। इस समूह ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है तथा इसकी सिफारिशें सिद्धान्ततः स्वीकार कर ली गई हैं। इसके क्रियान्वयन के तौर-तरीके तैयार किए जा रहे हैं।

131. भारतीय रुपए का अब एक नया प्रतीक चिह्न है जिसे केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों, कारोबारी कंपनियों और आम जनता द्वारा प्रयोग किए जाने के लिए अधिसूचित कर दिया गया है। इस प्रतीक चिह्न के अंकन वाली सिक्कों की नई शृंखला शीघ्र ही जारी की जाएगी। सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मानकों में इस प्रतीक चिह्न को शामिल करने के लिए यूनिटोड स्टैंडर्ड प्राधिकरण से संपर्क किया है।

V. बजट अनुमान 2011-12

अब, मैं 2011-12 के बजट अनुमानों पर आता हूँ।

132. सकल कर राजस्व प्राप्तियों के 9,32,440 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। यह 2010-11 के बजट अनुमानों से 24.9 प्रतिशत अधिक है। राज्यों को अंतरित किए जाने के बाद 2010-11 में केंद्र का निवल कर 6,64,457 करोड़ रुपए है। वर्ष 2011-12 के लिए कर-भिन्न राजस्व प्राप्तियां 1,25,435 करोड़ रुपए अनुमानित हैं।

133. वर्ष 2011-12 के लिए प्रस्तावित कुल व्यय 12,57,729 करोड़ रुपए है। यह वर्ष 2010-11 के बजट अनुमानों से 13.4 प्रतिशत अधिक है। व. अ. 2010-11 की तुलना में आयोजना व्यय 18.3 प्रतिशत की वृद्धि दिखाते हुए 4,41,547 करोड़ रुपए तथा आयोजना भिन्न व्यय 10.9 प्रतिशत की वृद्धि दिखाते हुए 8,16,182 करोड़ रुपए है। चूंकि वर्ष 2011-12 ग्यारहवीं योजना अवधि का आखिरी वर्ष है, मुझे यह बताते हुए खुशी है कि ग्यारहवीं योजना व्यय सामान्यतः इस योजना अवधि के लिए प्रत्याशित व्यय के 100 प्रतिशत से भी अधिक है।

134. वर्ष 2011-12 में राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को किए जाने वाले 2,01,733 करोड़ रुपए के कुल आयोजना तथा आयोजना भिन्न अंतरणों में बजट अनुमान 2010-11 की तुलना में 23 प्रतिशत वृद्धि की गयी है। इसमें तेरहवें वित्त आयोग द्वारा दी गई संस्तुति के अनुसार स्थानीय निकायों को वर्ष 2011-12 में दिए जाने वाले 13,713 करोड़ रुपए के अनुदान भी शामिल है।

135. माननीय सदस्यों को पता है कि मुझे, 3जी स्पैक्ट्रम नीलामियों से प्रत्याशित कर-भिन्न राजस्व अधिक मिलने के कारण, वर्ष 2010-11 में राजकोषीय संतुलन में और सुधार करने का मौका मिला था। मैं इस कार्य को और आगे बढ़ाना चाहता हूँ। जहाँ एक तरफ मैंने महत्वपूर्ण अवसंरचना और सामाजिक क्षेत्रों के लिए तथा सब्सिडियों पर व्यय भी पूरा करने के लिए, 50,000 करोड़ रुपए मुहैया कराए हैं, वहीं मैंने वर्ष 2010-11 में वित्तीय घाटा स.घ.उ. के 5.5 प्रतिशत के कम करके 5.1 प्रतिशत किया है। वर्ष 2011-12 के लिए, मैंने इसे स.घ.उ. के 4.6 प्रतिशत पर रखा है। यह पिछले बजट में प्रस्तुत राजकोषीय रूप-रेखा में इंगित वर्ष 2011-12 के मेरे स्वयं के लक्ष्य में हुए सुधारों को दर्शाता है। सदन में आज ही प्रस्तुत किए जा रहे मध्याह्निक राजकोषीय नीतिगत विवरण में, राजकोषीय घाटे के चलायमान लक्ष्यों को वर्ष 2012-13 के लिए 4.1 प्रतिशत तथा वर्ष 2013-14 के लिए 3.5 प्रतिशत रखा गया है।

136. अर्थव्यवस्था के वैश्विक संकट के दौर के बाद सरकार के राजस्व घाटे की अप्रिय स्थिति पर चिंता प्रकट की गई है। राजस्व घाटा, वर्ष 2010-11 में 4 प्रतिशत लक्ष्य की तुलना में, स. घ. उ. का 3.4 प्रतिशत अनुमानित है। पिछले कुल वर्षों में राज्यों को अंतरण तथा अन्य विकासोन्मुख व्यय काफी बढ़ गया है। इन्हें राजस्व व्यय के नाम से वर्गीकृत किया जाता है, हालांकि इन अंतरणों का अच्छा खासा भाग पूंजीगत व्यय की प्रकृति का होता है। वर्ष 2010-11 में, ऐसे राजस्व व्ययों से 90,792 करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय की प्रकृति के थे। इसी प्रकार, वर्ष 2011-12 में पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए

सहायता अनुदान 1.47 लाख करोड़ रुपए है। इन्हें अब बजट दस्तावेजों में अलग से दर्शाया जाता है। इन बजट प्रावधानों के मद्देनजर, "प्रभावी राजस्व घाटा", 2010-11 और 2011-12 के संशोधित अनुमानों में क्रमशः 2.3 प्रतिशत एवं 1.8 प्रतिशत अनुमानित है।

137. मैंने, अपने पिछले बजट में यह बताया था कि सरकार तेल तथा उर्वरक कंपनियों को सब्सिडी के एवज में बांड जारी करने से बचेगी। मैंने इसका पालन किया है। ऐसा करके सभी सब्सिडी सम्बन्धी देनदारियों को अपने राजकोषीय हिसाब-किताब में लिया जा रहा है।

138. 2011-12 में राजकोषीय घाटा स.घ.उ. के 4.6 प्रतिशत की दर पर 4,12,817 करोड़ रुपए अनुमानित है। राजकोषीय घाटे के लिए जिम्मेवार अन्य विभिन्न वित्तीय मदों को ध्यान में रखते हुए, 2011-12 में सरकार का निवल वास्तविक बाजार उधार 3.43 लाख करोड़ रुपए होगा। इस उधार का एक हिस्सा लगभग 15,000 करोड़ रुपए ट्रेजरी बिलों के जरिए वित्तपोषित किया जाना प्रस्तावित है। तदनुसार स. घ.उ. के अनुपात के रूप में केन्द्रीय सरकार का ऋण वर्ष 2011-12 के लिए 44.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जबकि यह तेरहवें वित्त आयोग द्वारा 52.5 प्रतिशत सुझाया गया है।

भाग ख

माननीय अध्यक्ष महोदय,

मैं, अब अपने कर प्रस्ताव पेश करता हूँ।

139. इन प्रस्तावों को तैयार करते समय मेरी प्राथमिकताएं करों को उदार, करदाताओं के लिए भुगतान सहज और कर समाहर्ता के लिए कर-संग्रहण आसान बनाने की है।

VI. प्रत्यक्ष कर

मैं, अब प्रत्यक्ष करों पर आता हूँ।

140. चूंकि प्रत्यक्ष दरों पर सरकार की नीति की रूप-रेखा प्रत्यक्ष कर संहिता (डीटीसी) में दी गई है जो संसद के समक्ष है, इसलिए इन उपायों के मेरे प्रस्ताव सीमित हैं जिन पर तत्काल ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

141. पिछले वर्ष मैंने कर स्लैबों को व्यापक बनाकर व्यक्ति करदाताओं को राहत प्रदान की थी। डीटीसी दरों के आस-पास रहते हुए, मैं वैयक्तिक करदाताओं की सामान्य श्रेणी के लिए छूट सीमा इस वर्ष 1,60,000 रुपए से बढ़ाकर 1,80,000 रुपए करने का प्रस्ताव करता हूँ। इस उपाय से इस श्रेणी के हर करदाता को 2,000 रुपए की एक समान कर राहत मिलेगी।

142. वरिष्ठ नागरिक हमारे विशेष ध्यान दिए जाने के पात्र हैं। मैं यह प्रस्ताव करता हूँ कि :

- अर्हक आयु 65 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष करना;
- छूट सीमा 2,40,000 रुपए से बढ़ाकर 2,50,000 रुपए करना;
- बहुत वरिष्ठ नागरिकों, 80 वर्ष एवं उससे अधिक, की एक नई श्रेणी सृजित करना जो 5,00,000 रुपए की उच्चतर छूट सीमा की हकदार होगी।

143. कारपोरेट्स की स्थिति में, अधिभारों को चरणों में समाप्त करने की मेरी पहल जारी है। मैं, घरेलू कंपनियों पर लागू 7.5 प्रतिशत के अधिभार को घटाकर 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ। साथ ही, मैं न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) की विद्यमान दर को 18 प्रतिशत से बढ़ाकर बड़ी लाभ का 18.5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ, ताकि मैट की प्रभावी दर इसी स्तर पर बनायी रखी जा सके। निगम कर देनदारियों की समान हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के उपाय के रूप में मैं विशेष आर्थिक क्षेत्रों के विकासकर्ताओं तथा इन क्षेत्रों में कार्यरत यूनिटों पर मैट लगाने का प्रस्ताव करता हूँ।

144. अवसंरचना के वित्तपोषण के लिए विदेशी निधियां जुटाने हेतु, मैं यह प्रस्ताव करता हूँ कि:

- अधिसूचित अवसंरचना ऋण निधि के रूप में विशेष साधनों का सृजन किया जाए;
- इन निधियों के उधारों पर विषय संबंधी ब्याज पर 20 प्रतिशत की आस्थगन कर दर (विदहोलिंडिंग टैक्स पर) को घटाकर 5 प्रतिशत करना; और
- निधि की आय को कर-मुक्त करना।

145. बचतों को प्रोत्साहित करने और अवसंरचना के लिए निधियां जुटाने के लिए, केंद्र सरकार ने 2010-11 में दीर्घावधिक अवसंरचना बांडों में निवेश हेतु 20,000 रुपए की अतिरिक्त कटौती की अधिसूचना जारी की थी। मैं इसे और एक वर्ष के लिए बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूँ।

146. यह निवेदन किया गया है कि निवासी करदाताओं के हाथ में विदेशी लाभांशों का पूरी दर पर कराधान भारत में उनके प्रत्यपण के लिए प्रोत्साहनजनक नहीं है तथा वे विदेश में निवेश करते हैं। वर्ष 2011-12 हेतु, मैं भारतीय कंपनी द्वारा उसकी विदेशी सहायक कंपनी से प्राप्त किए गए लाभांशों पर 15 प्रतिशत की अपेक्षाकृत कम दर पर कर लगाने का प्रस्ताव करता हूँ। मुझे आशा है, ये निधियां अब भारत में आएंगी।

147. कृषि क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, मैं, उर्वरकों का उत्पादन कर रहे व्यवसायों को निवेश से संबंधित कटौती का लाभ देने का प्रस्ताव करता हूँ।

148. आवास को महत्व को ध्यान में रखते हुए, मैं, अधिसूचित स्कीम के तहत वहनीय आवास बनाने में लगे व्यवसायों को भी निवेश आधारित कटौती का प्रस्ताव करता हूँ।

149. नवाचार के इस दशक में, मैंने राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं, विश्वविद्यालयों तथा प्रौद्योगिकी संस्थानों को वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए किए जाने वाले भुगतानों पर की जाने वाली भारत कटौती बढ़ाकर पिछले बजट में 175 प्रतिशत की थी। मैं इसे बढ़ाकर 200 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ।

150. विदेशी कर क्षेत्राधिकार से सूचना संग्रहण की अपनी व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए, मैं गैर-सरकारी क्षेत्राधिकार में स्थित इकाइयों जिन्हें सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाएगा, के साथ कारोबार को हतोत्साहित करने हेतु प्रतिरोधी उपायों के एक टूलबॉक्स की व्यवस्था करने का प्रस्ताव करता हूँ।

151. प्रत्यक्ष करों के संबंध में मेरे प्रस्तावों से इस वर्ष 11,500 करोड़ रुपए का निवल राजस्व घाटा होगा।

VII. अप्रत्यक्ष कर

मैं, अब अपने अप्रत्यक्ष कर संबंधी प्रस्तावों पर आता हूँ।

152. वर्ष 2010-11 में अप्रत्यक्ष करों में द्रुत वृद्धि को देखते हुए, मेरे पास केंद्रीय उत्पाद शुल्क कम करके उसी स्तरों पर लाने का विकल्प था, जो नवम्बर, 2008 में विद्यमान थे। मैंने दो कारणों से इसे नहीं चुना है। मैं बेहतर कारोबार लाभों को उच्चतर निवेश दरों में परिवर्तित होते देखना चाहता हूँ। मैं वस्तु एवं सेवा कर अपनाने के प्रति अपने दृष्टिकोण को बनाए रखना चाहता हूँ। अतः मैंने केंद्रीय उत्पाद शुल्क की मानक दर 10 प्रतिशत बनाए रखने का निर्णय लिया है।

153. मैं, वस्तु एवं सेवा कर को लागू करने के लिए जमीन तैयार करने हेतु कई छूटों में कटौती से शुरूआत करके केंद्रीय उत्पाद दर की संरचना में कतिपय परिवर्तन करने का प्रस्ताव करता हूँ। इस समय, ऐसी लगभग 100 वस्तुएँ हैं जिन्हें केंद्रीय उत्पाद शुल्क के साथ-साथ राज्य वैट से छूट प्राप्त है। इसके अलावा, 370 वस्तुएँ ऐसी हैं जिन्हें केंद्रीय उत्पाद शुल्क से छूट प्राप्त है किन्तु वैट लगता है। मैं, इन वस्तुओं में से 130 वस्तुओं पर मिली छूट को हटाने का प्रस्ताव करता हूँ। ये वस्तुएँ मुख्यतः उपभोक्ता वस्तु स्वरूप की हैं। शेष 240 वस्तुओं को, वस्तु एवं सेवा कर के अस्तित्व में आने के बाद, कर के दायरे में लाया जाएगा।

154. कर के दायरे में आने वाली 130 वस्तुओं पर 1 प्रतिशत का नाममात्र केंद्रीय उत्पाद शुल्क लगाया जा रहा है। इन वस्तुओं के विनिर्माण के लिए, सेनवैट क्रेडिट उपलब्ध नहीं होगा। बुनियादी खाद्य और ईंधन को छूट मिलती रहेगी। यह शुल्क बहुमूल्य धातुओं तथा रत्नों पर भी लागू नहीं होगा। आभूषण और स्वर्ण, चांदी एवं मूल्यवान धातुओं से बनी वस्तुओं के मामले में, यह लेवी केवल ब्रांड नाम से बेचे जाने वाली वस्तुओं पर लागू होगी।

155. अधिकांश राज्यों ने अपनी वैट की पात्रता दर 4 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत कर दी है। इसी के अनुरूप, मैं भी केंद्रीय उत्पाद शुल्क की सबसे कम दर को 4 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ।

156. तैयार वस्त्र और कपड़े से बनी वस्तुएँ इस समय वैकल्पिक उत्पाद शुल्क प्रणाली के अधीन आती हैं। यदि कोई विनिर्माता सेनवैट क्रेडिट का लाभ उठाना चाहता है, तभी उसे शुल्क अदा करना पड़ेगा। हमारा वस्त्र और कपड़े की वस्तुएँ निर्माण करने वाले उद्योग ने लम्बी यात्रा तय की है और हाल के वर्षों में अच्छी खासी वृद्धि दिखाई है। आधार विस्तार के भाग के रूप में, मैं वैकल्पिक लेवी को 10 प्रतिशत की एक समान दर पर अनिवार्य लेवी में बदलने का प्रस्ताव करता हूँ। हालाँकि, यह लेवी केवल ब्रांडेड वस्त्रों अथवा वस्तुओं पर लागू होगी और खुदरा ग्राहक के लिए दर्जों से अथवा आर्डर देकर बनवाए गए वस्त्रों अथवा वस्तुओं पर लागू नहीं होगी। वस्तुओं, पूंजीगत वस्तुओं तथा निविष्टि सेवाओं पर प्रदत्त कर का क्रेडिट इन उत्पादों के विनिर्माताओं के लिए उपलब्ध होगा। इस उद्योग के खंडित स्वरूप को ध्यान में रखते हुए, इन उत्पादों को पूरी एसएसआई छूट भी दी जा रही है। इन वस्तुओं का निर्यात, शून्य शुल्क दर पर जारी रहेगा।

157. आसियान देशों में विद्यमान सीमा-शुल्क की दरों के अनुरूप, अपनी भी सीमा-शुल्क दरें निश्चित करने की हमारी दीर्घावधिक प्रतिबद्धता रही है। सीमा-शुल्क की सर्वोच्च दर पिछले वर्षों में कम की गयी है तथा 10 प्रतिशत पर निश्चित की गई है। विश्व अर्थव्यवस्था में व्याप्त अनिश्चितताओं को देखते हुए, मैं इसकी सर्वोच्च दर इसके विद्यमान स्तर पर ही रखना चाहता हूँ। तथापि, 2 प्रतिशत, 2.5 प्रतिशत और 3 प्रतिशत की तीन दरों को एकीकृत करके 2.5 प्रतिशत के मध्यम स्तर पर रखने के लिए कुछ यौक्तिकीकरण किया जा रहा है।

158. अब मैं उन प्रस्तावों पर आता हूँ जिनका लक्ष्य उन कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों को प्रोत्साहन देना है, जिन पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है।

कृषि और संबंधित क्षेत्र

159. माननीय सदस्यों को स्मरण होगा कि पिछले बजट में, मैंने कृषि उपज हेतु भण्डारण और भाण्डागारण सुविधाओं की उपलब्धता में सुधार लाने तथा खाद्य प्रसंस्करण को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक उपायों की घोषणा की थी।

मुझे इन उपायों के प्रभावों पर उत्साहवर्धक फीडबैक प्राप्त हुआ है। मैं निम्नलिखित उपायों द्वारा इन छूटों का दायरा बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूँ :

- शीतागारों की अवसंरचना हेतु वातानुकूलन उपस्कर और रेफ्रिजरेशन पैनेलों पर उत्पाद शुल्क से पूरी छूट देना; और
- शीत भंडारों, मंडियों और भाण्डागारों में प्रयुक्त उपस्कर में उत्पाद शुल्क से पूरी छूट में कन्वेयर बेल्टों को शामिल करना।

160. पिछले बजट में विनिर्दिष्ट कृषि मशीनरी पर बुनियादी सीमा शुल्क की 5 प्रतिशत की रियायती दर दी गई थी। इस शुल्क में और कटौती करके इसे 2.5 प्रतिशत किया जा रहा है और यह रियायत ऐसी मशीनरी के कल-पुर्जों पर भी दी जा रही है ताकि उनके घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिल सके।

161. लघु-सिंचाई, विशेषकर शुष्क भूमि में खेती के लिए सिंचाई का एक पर्यावरण अनुकूल और सक्षम साधन है। मैं, लघु सिंचाई के उपस्कर पर बुनियादी सीमा-शुल्क 7.5 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ।

162. तेल निकाली गई धान की भूसी की खली पशु चारे का एक महत्वपूर्ण अंश है और इसकी बेहतर उपलब्धता का दुग्ध उत्पादन पर सकारात्मक प्रभाव होगा। मैं इस वस्तु को बुनियादी शुल्क से पूरी छूट देने का प्रस्ताव करता हूँ। साथ ही, इसके निर्यात को हतोत्साहित करने के लिए 10 प्रतिशत का निर्यात शुल्क लगाया जाएगा।

विनिर्माण सैक्टर

163. विनिर्माण क्षेत्र के लिए, मेरे प्रस्तावों में आयातों की अपेक्षा घरेलू मूल्य वर्धन को बढ़ावा देने, शुल्क प्रतिलोमन और

विसंगतियों को दूर करने तथा घरेलू उद्योग को बराबरी के अवसर प्रदान करने का प्रयास किया गया है। मुख्य प्रस्ताव निम्नलिखित हैं :

- कच्चे रेशम (बिना धुना हुआ) पर बुनियादी सीमा-शुल्क 30 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करना;
- कतिपय कपड़ा अन्तर्वर्ती वस्तुओं तथा रसायनों हेतु अन्तर्धारितों, लौह मिश्रधातु और कागज पर बुनियादी सीमा-शुल्क 5 प्रतिशत से घटाकर 2.5 प्रतिशत करना;
- कतिपय तकनीकी फाइबर और धागे (यार्न) के विनिर्माण में प्रयुक्त कुछ विनिर्दिष्ट वस्तुओं पर बुनियादी सीमा-शुल्क 7.5 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करना;
- स्टेनलेस स्टील स्क्रैप को बुनियादी सीमा-शुल्क से पूरी छूट देना;
- सिरिजों और सुइयों के विनिर्माण हेतु विनिर्दिष्ट कच्ची सामग्री पर आयात शुल्क घटाकर 5 प्रतिशत बुनियादी और 4 प्रतिशत सीवीडी करना;
- मोबाइल हैंडसेटों के विनिर्माण में प्रयुक्त पुर्जों, अवयवों और सहायक यंत्रों को उपलब्ध रियायत को 31 मार्च, 2012 तक बढ़ाना तथा कुछ और वस्तुओं को इसके दायरे में शामिल करना;
- विनिर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक अवयवों, जो बुनियादी सीमा-शुल्क से पूरी तरह मुक्त हैं, के विनिर्माण के लिए कच्ची सामग्री की सूची में विस्तार करना; और
- इंक-जेट और लेजर-जेट प्रिंटरों के पुर्जों पर उत्पाद शुल्क (और अब से सीवीडी) 10 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करना।

164. लौह अयस्क पर पिण्डों के मामले में 15 प्रतिशत और परिष्कृत के मामले में 5 प्रतिशत का निर्यात शुल्क लगाया जाता है। यह एक प्राकृतिक संसाधन है जिसे परिरक्षित किए जाने की आवश्यकता है। मैं, सभी प्रकार के लौह अयस्क के लिए निर्यात शुल्क बढ़ाने और इसे 20 प्रतिशत यथामूल्य पर एक समान करने का प्रस्ताव करता हूँ। लौह अयस्क को मूल्य-वर्धित, गुटिकाओं के स्वरूप में निर्यात किया जाता है। परिष्कृत लौह धातु के लिए मूल्यवर्धन प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने के लिए लौह अयस्क गुटिकाओं को निर्यात शुल्क से पूर्ण छूट दी जा रही है।

165. सीमेंट उद्योग को राहत के उपाय के रूप में, मैं, मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों के स्थान पर, मिश्रित दरों को लाने का प्रस्ताव करता हूँ जिनमें कुछ यौक्तिकीकरण सहित यथामूल्य और विशिष्ट घटक होंगे। इस उद्योग के दो अतिमहत्वपूर्ण कच्ची सामग्रियाँ अर्थात् पेटकोक और जिप्सम पर बुनियादी सीमा-शुल्क घटाकर 2.5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है।

166. सरकार के वित्तीय समावेशन एजेन्डा को आगे बढ़ाने के लिए, मैं कैश डिस्पेन्सरों को बुनियादी सीमा-शुल्क से पूरी तरह मुक्त करने का प्रस्ताव करता हूँ। उनके घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, इन मशीनों के पुर्जों को भी पूरी छूट दी जा रही है।

पर्यावरण

167. पिछले बजट में इलेक्ट्रिकल वाहनों के विनिर्दिष्ट पुर्जों पर वास्तविक-प्रयोक्ता आधार पर बुनियादी सीमा-शुल्क से पूर्ण छूट और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क की 4 प्रतिशत की रियायती दर दी गई थी। मैं इस रियायत को इन विनिर्माताओं द्वारा आयातित वैद्युतियों पर बदलाव बाजार हेतु बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूँ।

168. ईंधन सैल अथवा हाइड्रोजन सैल प्रौद्योगिकी आटोमोबाइल सेक्टर के लिए एक उदीयमान हरित प्रौद्योगिकी है। मैं, इस प्रौद्योगिकी पर आधारित वाहनों पर 10 प्रतिशत का रियायती उत्पाद शुल्क लगाने का प्रस्ताव करता हूँ।

169. हाइब्रिड वाहनों पर 10 प्रतिशत की रियायती उत्पादन शुल्क दर लगती है, लेकिन उनके महत्वपूर्ण पुर्जों/सब एसेम्बलियों पर आयात की निर्भरता अभी भी बहुत अधिक है। यह प्रस्ताव है कि इन वाहनों के विनिर्दिष्ट पुर्जों को बुनियादी सीमा-शुल्क और विशेष सीवीडी से पूरी छूट दी जाए। इसके अतिरिक्त, उनके घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए, 5 प्रतिशत की उत्पाद शुल्क की रियायती दर निर्धारित की जा रही है।

170. हरित उत्पादों की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए, एक प्लग-इन किट लगा कर जीवाश्म ईंधन वाहनों को हाइब्रिड वाहनों में बदलने हेतु, एक स्वदेशी प्रौद्योगिकी विकसित की गई है। मैं, इन किटों और उनके पुर्जों पर उत्पाद शुल्क 10 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ।

171. पिछले बजट में, एलईडी लाइटों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए, उन पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 8 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत किया गया था। इन लाइटों के मूल अवयव अर्थात् एलईडी पर 10 प्रतिशत का शुल्क (इसीलिए सीवीडी) तथा 4 प्रतिशत का विशेष सीवीडी लगता है। एलईडी पर उत्पाद शुल्क घटाकर 5 प्रतिशत किया जा रहा है और विशेष सीवीडी से पूरी छूट दी जा रही है।

172. सौर लालटेन की वजह से दूरवर्ती गाँवों के हमारे देशवासियों को हरित प्रौद्योगिकी के घटनाक्रमों में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त होता है। ऐसी लालटेनों पर लगाए जाने वाले बुनियादी सीमा-शुल्क को 10 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया जा रहा है। सौर मॉड्यूलों/सेलों के विनिर्माण में इस्तेमाल होने वाले कुछ और पुर्जों पर बुनियादी सीमा-शुल्क को घटाकर शून्य किया जा रहा है।

173. पर्यावरण संबंधी सोच-विचारों में ऐसे उत्पाद के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की माँग की जाती है, जिनमें जल की खपत कम हो और मिट्टी के लिए नुकसान न हो। इस संबंध में कपड़ा धुलाई के साबुन के विनिर्माण में क्रूड पाम स्टीयरिन को बुनियादी सीमा-शुल्क से पूरी छूट प्रदान की जा रही है।

174. चर्म उद्योग में टैनिंग-पूर्व अथवा टैनिंग प्रक्रियाओं में ऐसे रसायनों का प्रयोग किया जाता है जो प्रदूषण फैलाते हैं। हरित प्रक्रियाओं के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए, टैनिंग-पूर्व प्रक्रियाओं के लिए एन्जाइन आधारित सामग्री को बुनियादी उत्पाद-शुल्क से पूरी छूट प्रदान की जा रही है।

अवसंरचना

175. मौजूदा मेगा अथवा अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं के विस्तार के लिए आयातित पूँजीगत वस्तुओं पर 2.5 प्रतिशत का रियायती बुनियादी सीमा-शुल्क लगता है और ये सीवीडी से पूरी तरह छूट प्राप्त हैं। इससे घरेलू आपूर्तिकर्ताओं जिन्हें ऐसी परियोजनाओं संबंधी आपूर्तियों पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क देना होता है, में असंतोष की भावना पनपती है। मैं, एक समतुल्य उत्पादन शुल्क छूट देकर इस विसंगति को दूर करने का प्रस्ताव करता हूँ।

176. सड़कों के सतह निर्माण के लिए जैव-आधारित डामर एक नई हरित प्रौद्योगिकी है। जैव-आधारित डामर और राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में इसके उपयोग हेतु विनिर्दिष्ट मशीनरी को बुनियादी सीमा-शुल्क से पूरी छूट प्रदान की जा रही है। राजमार्गों के निर्माण में अपेक्षित सुरंग खोदने की मशीनों पर भी यह छूट प्रदान की जा रही है।

अन्य प्रस्ताव

177. सार्वजनिक संग्रहालय अथवा राष्ट्रीय संस्था में प्रदर्शनी हेतु आयात की जाने वाली कलाकृतियों और पुरावशेषों को सीमा-शुल्क से छूट प्राप्त है। हाल के वर्षों में, कई निजी संस्थाओं, अलाभकारी संगठनों और अन्य परम्परागत और समकालीन दोनों कलाओं को बढ़ावा देने और लोकप्रिय बनाने के कल्याणकारी कार्य में सम्मिलित हुए हैं। कुछ व्यक्ति विदेशों में भारतीय कला और पुरावशेषों की पारम्परिक कृतियों का पता लगाने और उन्हें वापस अपने देश में लाने में सक्रिय रहे हैं। ऐसे प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए, मैं, कला कृतियों और पुरावशेषों तथा निजी कलाकृति दीर्घाओं अथवा इसी प्रकार के आम जनता के लिए खुले परिसरों में प्रदर्शनी अथवा प्रदर्शन हेतु आयात के लिए इस छूट के कार्यक्षेत्र को विस्तार का प्रस्ताव करता हूँ। संस्कृति विभाग इस योजना का ब्यौरा अलग से अधिसूचित करेगा।

178. पोत मरम्मत इकाइयों के लिए आवश्यक अतिरिक्त कल-पुर्जों और पूँजीगत वस्तुओं को आयात शुल्क से पूरी छूट प्रदान की गई है। यह छूट पोत मालिकों द्वारा किए गए आयातों पर भी दी जा रही है।

179. वर्तमान में, 5 प्रतिशत का रियायती बुनियादी सीमा-शुल्क और 5 प्रतिशत का सीवीडी अखबार प्रतिष्ठानों द्वारा आयात किए जाने वाले हाई-स्पीड प्रिंटिंग प्रेसों पर लागू है, जिसे मेलरूम इक्विपमेंट के आयात पर भी दिया जा रहा है।

180. भारतीय फिल्म उद्योग ने अनुरोध किया है कि सिनेमाटोग्राफिक फिल्मों के कलर, अनएक्सपोज्ड जम्बो रोलस का विनिर्माण अपने देश में नहीं किया जाता है, इनका आयात करना पड़ता है। मैं 400 फीट और 1000 फीट के जम्बो रोलस को उत्पाद शुल्क से पूरी छूट देकर सीवीडी से मुक्त करने का प्रस्ताव करता हूँ।

181. मैं कारखाना निर्मित एम्बुलेंसों के लिए उत्पाद शुल्क से मौजूदा रिफंड-आधारित रियायत के स्थान पर तत्काल रियायत प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूँ। रिफंड आधारित रियायत ऐसी टैक्सियों को उपलब्ध है जिनमें बैठने की क्षमता ड्राइवर सहित 7 व्यक्तियों से अधिक नहीं है। मैं यह रियायत ऐसे वाहनों को देने का प्रस्ताव करता हूँ, जिनमें बैठने की क्षमता ड्राइवर सहित 13 व्यक्ति से अधिक नहीं है।

182. मैं निम्नलिखित कुछ अन्य राहत उपायों का प्रस्ताव करता हूँ :

- कच्चे पिस्ता पर बुनियादी सीमा-शुल्क 30 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत करना;
- अगरबत्ती के लिए बाँस पर बुनियादी सीमा-शुल्क 30 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत करना;
- होमियोपैथिक दवाओं के विनिर्माण के लिए लैक्टोज पर बुनियादी सीमा-शुल्क 25 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत करना; और
- सैनिट्री नैपकिनों, बेबी और एडल्ट डायपरों पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 10 प्रतिशत से घटाकर 1 प्रतिशत करना।

183. सीमा-शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क संबंधी मेरे प्रस्तावों से इस वर्ष में 7,300 करोड़ रुपए का निवल राजस्व लाभ होने का अनुमान है।

VIII. सेवा कर

184. सेवा कर के वास्तविक संग्रहण से इस क्षेत्र की पूरी क्षमता का पता नहीं चलता है। सेवा कर की 10 प्रतिशत की मानक दर को बनाए रखते हुए, मैं वर्तमान सेवा कर प्रणाली और इसके उत्तरवर्ती वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में निम्नलिखित उपायों से तालमेल बैठाना चाहता हूँ :

- कराधार के विस्तार हेतु कर के दायरे में कुछ नई सेवाओं को लाना और साथ ही यह सुनिश्चित करना कि इसका प्रभाव पहले की तरह समाज के ऐसे वर्गों पर हो जिनमें भुगतान करने की क्षमता हो;
- सेवा की मौजूदा श्रेणियों के कार्यक्षेत्र का उपयुक्त रूप से विस्तार करना और उसे युक्तियुक्त बनाना;
- सेवाओं के आयात और मूल्यांकन संबंधी कतिपय प्रावधानों को युक्तियुक्त बनाना;
- इन्पुट क्रेडिटों और आउटपुट कर के बीच अधिक वास्तविक संतुलन बनाने तथा वस्तुओं एवं सेवाओं में योजना के उपबंधों में तालमेल बैठाने के लिए, सेनवैट क्रेडिट योजना के प्रावधानों में संशोधन करना;
- इस संदेश को पुष्ट करने के लिए दण्डात्मक प्रावधानों को युक्ति-संगत बनाना कि ईमानदार करदाताओं की मदद की जाएगी और चूककर्ताओं पर कड़ी कार्रवाई होगी; और
- ऐसी सेवाओं के सम्बन्ध में कराधान अंक नियमों को अपनाना जो कर संग्रह के सम्बन्ध में आधार को "नकद" से "उपचय" आधार की ओर ले जाएगा जैसा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के मामले में है।

185. मैं, निम्नलिखित सेवाओं पर सेवा कर लगाने का प्रस्ताव करता हूँ :

- होटल आवास 50 प्रतिशत की छूट के साथ जबकि यह 1000 रुपए प्रति दिवस के घोषित टैरिफ से अधिक है ताकि प्रभाषित राशि के केवल 5 प्रतिशत का प्रभावी भार पड़े; और

- ऐसे एअर कंडीशन युक्त रेस्तराँओं को जिनके पास शराब परोसने का लाइसेंस है, 70 प्रतिशत की छूट देना। इस प्रकार प्रभावी भार बिल का 3 प्रतिशत होगा।

186. मैंने 2010-11 में स्वास्थ्य परीक्षण अथवा उपचार पर सेवा कर लगाया था। इसके परिणामस्वरूप, ऐसी लेवी से उन व्यक्तियों के मध्य विभेदक उपचार की शुरुआत हुई जो स्वयं भुगतान करते हैं और अन्य के सम्बन्ध में भुगतान किसी बीमा कम्पनी अथवा व्यावसायिक इकाई द्वारा किया जाता है। इस प्रकार 25 अथवा इससे अधिक बिस्तरों वाले एअर कंडीशन की सुविधा युक्त अस्पतालों द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सभी सेवाओं पर कर लगाकर इसको हटाने का प्रस्ताव करता हूँ। यद्यपि यह कर मंहने उपचार पर लगाया जाता है, मैं 50 प्रतिशत की छूट द्वारा इस अप्रिय स्थिति को स्वीकार करने का प्रस्ताव करता हूँ ताकि वास्तविक भार को सेवा मूल्य के 5 प्रतिशत पर रखा जा सके। साथ ही, मैं, इस लेवी को सभी प्रकार के नैदानिक परीक्षणों पर समान छूट की दर-सहित लगाने का प्रस्ताव करता हूँ। तथापि, सभी सरकारी अस्पताल इस लेवी से बाहर रहेंगे।

187. मैं इकॉनोमी श्रेणी द्वारा घरेलू हवाई यात्रा पर 50 रुपए और अंतरराष्ट्रीय यात्राओं पर 250 रुपए का सेवा कर लगाने का प्रस्ताव करता हूँ। मैं घरेलू क्षेत्र पर 10 प्रतिशत की मानक दर पर उच्च श्रेणियों द्वारा की गयी यात्रा पर कर लगाने का भी प्रस्ताव करता हूँ ताकि इसे उच्च श्रेणियों द्वारा की गयी अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा के समान स्तर पर लाया जा सके।

188. निवेश के क्षेत्र में जीवन बीमा कम्पनियों द्वारा मुहैया करायी गयी सेवाओं को भी, यूलिप की ही तर्ज पर, कर दायरे में लाने का प्रस्ताव है। मैं, विधि सेवाओं के क्षेत्र में विस्तार का प्रस्ताव करता हूँ और इस हेतु व्यावसायिक इकाइयों द्वारा व्यक्तियों को तथा प्रतिनिधि के रूप में व्यावसायिक इकाइयों को प्रदत्त की जाने वाली विवाचन सेवाओं के द्वारा व्यावसायिक इकाइयों को प्रदत्त की जाने वाली सेवाओं को इसमें शामिल किया जाएगा। तथापि, व्यक्तियों द्वारा अन्य व्यक्तियों को प्रदत्त सेवाओं पर कोई कर नहीं लगेगा।

189. कतिपय सेवाओं के क्षेत्र में, मुख्यतः यौक्तिकीकरण अथवा विस्तार के जरिए, कतिपय अन्य परिवर्तनों अथवा मौजूदा खामियों को समाप्त करने की गुंजाइश है। मैं पुनः उनके विस्तार पर जाकर यहां सदन का बहुमूल्य समय नहीं लेना चाहूंगा।

190. विश्वसनीय मूल्यवर्धित कर की मजबूती पिछले स्तर पर भुगतान किए गए कर क्रेडिट के मुक्त प्रवाह पर निर्भर करती है। जटिलताओं की वजह से, कई निविष्टियों अथवा निविष्टि सेवाओं के क्रेडिट की उपलब्धता पर कई कानूनी विवाद हैं। स्पष्ट परिभाषाओं की व्याख्या करके इन प्रावधानों को युक्तिसंगत बनाया जा रहा है ताकि निविष्टियों तथा निविष्टि सेवाओं के क्षेत्र जो अर्हक हैं अथवा जो नहीं हैं, को स्पष्ट किया जा सके। छूट के लिए सेनवेट, क्रेडिट का आवंटन और कराधेय वस्तुओं तथा सेवाओं को भी सरल तथा कारगर बनाया जा रहा है।

191. सेवाकर में निर्धारितियों की संख्या कई गुना बढ़ी है। मेरा अनुभव है कि उनमें से अधिकांश व्यक्ति अथवा छोटे कारोबार वाले लघु प्रोप्राइटर हैं, वे अपने परिसरों की लेखा परीक्षा होने पर,

लेखा-परीक्षा अवधि के दौरान अपनी गतिविधियों अन्यत्र करने लगते हैं। इसलिए, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि 60 लाख रुपए तक का कारोबार करने वाले सभी व्यक्तियों और एकल प्रोप्राइटर करदाताओं को लेखा परीक्षा की औपचारिकताओं से मुक्त रखा जाए। इससे बहुत से कर दाताओं को राहत मिलेगी। मैं, सभी ऐसे निर्धारितियों को भी जिनका कारोबार 60 लाख रुपए तक है, विलम्बित भुगतान पर ब्याज में 3 प्रतिशतांक का लाभ देना चाहता हूँ।

192. स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करने के हमारे दबाव को देखते हुए, सेवाकर के दण्डात्मक उपबंधों को युक्तिसंगत बनाया जा रहा है। इस कार्ययोजना का एक महत्वपूर्ण संघटक उन लोगों पर अपेक्षाकृत कठोर कार्रवाई करना है जिन्होंने अपना रिकार्ड साफ-सुथरा रखा है लेकिन अपनी कर देयता के निष्पादन में वे कहीं कमजोर पड़ जाते हैं। इसको साथ-साथ, जान बूझकर अपवंचन करने वाले लोगों पर, जो व्यावसायिक कारोबार रिकार्ड नहीं रखते हैं, के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। केन्द्रीय उत्पाद तथा सीमा-शुल्क कानूनों में भी इसी प्रकार के परिवर्तन किए जा रहे हैं। इन उपबंधों का ब्यौरा वित्त विधेयक में दे दिया गया है।

193. सेवाकर से सम्बद्ध मेरे प्रस्तावों के परिणामस्वरूप इस वर्ष 4,000 करोड़ रुपए का निवल राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है।

194. कई विशेषज्ञों का तर्क है लघु निषेधात्मक सूची पर आधारित सेवाओं पर कर लगाना वांछनीय होगा ताकि कई अनछुए क्षेत्रों को कर दायरे में लाया जा सके। ऐसा दृष्टिकोण सम्पूर्ण राष्ट्र में लागू किए जाने वाले वस्तु एवं सेवाकर के लिए पर्याप्त रूप से प्रेरक होगा। मैं, इस विषय पर सार्वजनिक बहस प्रारम्भ करने का प्रस्ताव करता हूँ ताकि वस्तु एवं सेवाकर की अवधारणा को अन्तिम रूप दिया जा सके।

195. सीमा-शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तथा सेवाकर में परिवर्तनों को प्रभावी बनाने से सम्बद्ध अधिसूचनाओं की प्रतियों को, यथा समय, सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

196. मेरे प्रत्यक्ष कर संबंधी प्रस्तावों के परिणामस्वरूप इस वर्ष 11,500 करोड़ रुपए की राजस्व हानि होने का अनुमान है। अप्रत्यक्ष कर संबंधी प्रस्तावों के फलस्वरूप, 11,300 करोड़ रुपए की निवल राजस्व प्राप्ति होने का अनुमान है। इस प्रकार बजट में 200 करोड़ रुपए की निवल हानि रह जाती है।

197. उभरती अर्थव्यवस्था के रूप में भारत, जिसकी आवाज विश्व में सुनी जाती है, इस दशक की दहलीज पर खड़ा है और जिसमें प्रचुर संभावनाएं हैं। हमें हाल के दबावों तथा तनावों के आड़े आने से बचना होगा ताकि ये संभावनाओं को वास्तविकताओं में बदलने में व्यवधान उत्पन्न न करें। हम सभी तहे दिल से ऐसे भारत का निर्माण करें जो निकट भविष्य में विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में प्रवेश करेगा।

अध्यक्ष महोदया, इन्हीं शब्दों के साथ मैं यह बजट सदन को समर्पित करता हूँ।"

शक्तिकान्ता दास, अपर सचिव (बजट)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(Budget Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th February, 2011

No. F.2(13)-B(D)/2011.—The following is published for general information :—

“Budget 2011-2012

Speech of

Pranab Mukherjee

Minister of Finance

February 28, 2011

Madam Speaker,

I rise to present the Union Budget for 2011-12.

We are reaching the end of a remarkable fiscal year. In a globalised world with its share of uncertainties and rapid changes, this year brought us some opportunities and many challenges as we moved ahead with steady steps on the chosen path of fiscal consolidation and high economic growth.

2. Our growth in 2010-11 has been swift and broad-based. The economy is back to its pre-crisis growth trajectory. While agriculture has shown a rebound, industry is regaining its earlier momentum. Services sector continues its near double digit run. Fiscal consolidation has been impressive. This year has also seen significant progress in those critical institutional reforms that would set the pace for double-digit growth in the near future.

3. While we succeeded in making good progress in addressing many areas of our concern, we could have done better in some others. The total food inflation declined from 20.2 per cent in February 2010 to less than half at 9.3 per cent in January 2011 but it still remains a concern. In the medium-term perspective, our three priorities of sustaining a high growth trajectory; making development more inclusive; and improving our institutions, public delivery and governance practices, remain relevant. These would continue to engage the Indian policy-planners for some time. However, there are some manifestations of these challenges that need urgent attention in the short-term.

4. Though we have regained the pre-crisis growth momentum, there is a need to effect adjustments in the composition of growth on demand and supply side. We have to ensure that along with private consumption, the revival in private investment is sustained and matches pre-crisis growth rates at the earliest. This requires a stronger fiscal consolidation to enlarge the resource space for private enterprise and addressing some policy constraints. We also have to improve the supply response of agriculture to

the expanding domestic demand. Determined measures on both these issues will help address the structural concerns on inflation management. It will also ensure a more stable macro-economic environment for continued high growth.

5. The UPA Government has significantly scaled up the flow of resources to rural areas to give a more inclusive thrust to the development process. The impact is visible in the new dynamism of our rural economy. It has helped India navigate itself rapidly out of the quagmire of global economic slowdown. Yet, there is much that still needs to be done, especially in rural India. We have to reconcile legitimate environmental concerns with necessary developmental needs. Above all, there is the ‘challenge of growing aspiration’ of a young India.

6. To address these concerns, I do not foresee resources being a major constraint, at least not in the medium-term. However, the implementation gaps, leakages from public programmes and the quality of our outcomes are a serious challenge.

7. Certain events in the past few months may have created an impression of drift in governance and a gap in public accountability. Even as the Government is engaged in addressing specific concerns emanating from some of these events in the larger public interest and in upholding the rule of law, such an impression is misplaced. We have to seize in these developments, the opportunity to improve our regulatory standards and administrative practices. Corruption is a problem that we have to fight collectively.

8. In a complex and rapidly evolving economy, the Government can not profess to be the sole repository of all knowledge. Indeed, in a democratic policy, it stands to benefit from inputs from colleagues on both sides of the House. They must lend their voice and expertise to influence public policy in the wider national interest. In some areas, good results depend on coordinated efforts of the Centre and the State Governments and in some others, on favourable external developments.

9. I see the Budget for 2011-12 as a transition towards a more transparent and result oriented economic management system in India. We are taking major steps in simplifying and placing the administrative procedures concerning taxation, trade and tariffs and social transfers on electronic interface, free of discretion and bureaucratic delays. This will set the tone for a newer, vibrant and more efficient economy.

10. At times the biggest reforms are not the ones that make headline, but the ones concerned with the details of governance, which affect the everyday life of *aam aadmi*. In preparing this year's Budget, I have been deeply conscious of this fact. I am grateful for the able guidance of the Hon'ble Prime Minister and the strong support lent by UPA Chairperson Smt. Sonia Gandhi in my endeavour. I would now begin with a brief overview of the economy.

I. Overview of the Economy

11. On last Friday, I laid on the table of the House the Economic Survey 2010-11, which gives a detailed analysis of the economic situation of the country over the past 12 months. The Gross Domestic Product (GDP) of India is estimated to have grown at 8.6 per cent in 2010-11 in real terms. In 2010-11 agriculture is estimated to have grown at 5.4 per cent, industry at 8.1 per cent and services at 9.6 per cent. All three sectors are contributing to the consolidation of growth. More importantly, the economy has shown remarkable resilience to both external and domestic shocks.

12. Our principal concern this year has been the continued high food prices. Inflation surfaced in two distinct episodes. At the beginning of the year, food inflation was high for some cereals, sugar and pulses. Towards the second half, while prices of these items moderated and even recorded negative rates of inflation, there was spurt in prices of onion, milk, poultry and some vegetables. Of late prices of onion have crashed in wholesale markets and we have had to remove the ban on their exports.

13. Despite improvement in the availability of most food items, consumers were denied the benefit of seasonal fall in prices normally seen in winter months. These developments revealed shortcomings in distribution and marketing systems, which are getting accentuated due to growing demand for these food items with rising income levels. The huge differences between wholesale and retail prices and between markets in different parts of the country are just not acceptable. These are at the expense of remunerative prices for farmers and competitive prices for consumers.

14. Monetary policy stance in 2010-11, while being supportive of fiscal policy, has succeeded in keeping core-inflation in check. As the transmission lag in monetary policy tends to be long, I expect the measures already taken by the RBI to further moderate inflation in coming months.

15. The developments on India's external sector in the current year have been encouraging. Even as the recovery in developed countries is gradually taking root, our trade performance has improved. Exports have grown at 29.4 per cent to reach US Dollar 184.6 billion, while imports at US Dollar 273.6 billion have recorded a growth of 17.6 per cent during April-January 2010-11, over the corresponding period last year. The current account deficit is around the 2009-10 level and poses some concerns because of the composition of its financing.

16. Policy-making in a globalised world has to take into account the likely international developments. To realise the desired outcomes, it is important that there is convergence in expectations of our investors, entrepreneurs and consumers on the macro-economic prospects of the economy. Against this backdrop, the Indian economy is expected to grow at 9 per cent with an outside band

of +/-0.25 per cent in 2011-12. I expect the average inflation to be lower next year and the current account deficit smaller and better managed with higher domestic savings rate and stable capital flows. While, like last year, I seek the blessings of *Lord Indra* to bestow on us timely and bountiful monsoons, I would pray to *Goddess Lakshmi* as well. I think it is a good strategy to diversify one's risks.

II. Sustaining Growth

17. In my last Budget, I had started rolling back the fiscal stimulus implemented over 2008-09 and 2009-10 to mitigate the impact of the global financial crisis on economic slowdown in India. In the course of the year, I have moved further on that path. I believe that a part of the current recovery must be stored away to build future resilience. Indeed, a counter cyclical fiscal policy is our best insurance against external shocks and localised domestic factors.

Fiscal Consolidation

18. The experience with Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2003 (FRBM Act) at Centre and the corresponding Acts at State level show that statutory fiscal consolidation targets have a positive effect on macro-economic management of the economy. In the course of the year the Central Government would introduce an amendment to the FRBM Act, laying down the fiscal road map for the next five years.

19. The Thirteenth Finance Commission has worked out a fiscal consolidation road map for States requiring them to eliminate revenue deficit and achieve a fiscal deficit of 3 per cent of their respective Gross State Domestic Product latest by 2014-15. It has also recommended a combined States' debt target of 24.3 per cent of GDP to be reached during this period. The States are required to amend or enact their FRBM Acts to conform to these recommendations.

20. The Government has been in the process of setting-up an independent Debt Management Office in the Finance Ministry. A Middle Office is already operational. As a next step, I propose to introduce the Public Debt Management Agency of India Bill in the next financial year.

Tax Reforms

21. The introduction of the Direct Taxes Code (DTC) and the proposed Goods and Services Tax (GST) will mark a watershed. These reforms will result in moderation of rates, simplification of laws and better compliance.

22. As Hon'ble Members are aware, the Direct Taxes Code Bill was introduced in Parliament in August 2010. After receiving the report of the Standing Committee, we shall be able to finalise the Code for its enactment during 2011-12. This has been a pioneering effort in participative legislation. The Code is proposed to be effective from April 1, 2012 to allow taxpayers, practitioners and administrators to fully understand the legislation and adjust to the revised procedures.

23. Unlike DTC, decisions on the GST have to be taken in concert with the States with whom our dialogue has made considerable progress in the last four years. Areas of divergence have been narrowed. As a step towards the roll-out of GST, I propose to introduce the Constitution Amendment Bill in this session of Parliament. Work is also underway on drafting of the model legislation for the Central and State GST.

24. Among the other steps that are being taken for the introduction of GST is the establishment of a strong IT infrastructure. We have made significant progress on the GST Network (GSTN). The key business processes of registration, returns and payments are in advanced stages of finalisation. The National Securities Depository Limited (NSDL) has been selected as technology partner for incubating the National Information Utility that will establish and operate the IT backbone for GST. By June 2011, NSDL will set up a Pilot portal in collaboration with eleven States prior to its roll out across the country.

Expenditure Reforms

25. The effective management of public expenditure is an integral part of the fiscal consolidation process. Expenditure has to be oriented towards the production of public goods and services. The extant classification of public expenditure between plan, non-plan, revenue and capital spending needs to be revisited. This is necessary as one recognises the importance of service sector and the knowledge economy for our development. A Committee under Dr. C. Rangarajan has been set up by the Planning Commission to look into these issues.

Subsidies

26. During the year 2010-11, the Nutrient Based Subsidy (NBS) policy was successfully implemented for all fertilisers except urea. The policy has been well received by all stakeholders, and the availability of fertilisers has improved. The extension of the NBS regime to cover urea is under active consideration of the Government.

27. The Government provides subsidies, notably on fuel and food grains, to enable the common man to have access to these basic necessities at affordable prices. A significant proportion of subsidised fuel does not reach the targeted beneficiaries and there is large scale diversion of subsidised kerosene oil. A recent tragic event has highlighted this practice. We have deliberated for long the modalities of implementing such subsidies. The debate now has to make way for decision. To ensure greater efficiency, cost effectiveness and better delivery for both kerosene and fertilisers, the Government will move towards direct transfer of cash subsidy to people living below poverty line in a phased manner.

28. A task force headed by Shri Nandan Nilekani has been set-up to work out the modalities for the proposed system of direct transfer of subsidy for kerosene, LPG and fertilisers. The interim report of the task force is expected by June 2011. The system will be in place by March 2012.

People's Ownership of PSUs

29. The Government's programme to broadbase the ownership of Central Public Sector Undertakings (CPSUs) has received an overwhelming response. The six public issues of CPSUs in the current financial year have attracted around 50 lakh retail investors.

30. As against a target of ₹40,000 crore, the Government will raise about ₹22,144 crore from disinvestment in 2010-11. A higher than anticipated realisation in non-tax revenues has led us to reschedule some of the divestment issues planned for the current year. I intend to maintain the momentum on disinvestment in 2011-12 by raising ₹40,000 crore. Let me reiterate here that the Government is committed to retain at least 51 per cent ownership and management control of the CPSUs, as stated earlier in my Budget speech for 2009-10.

Investment Environment

Foreign Direct Investment

31. To make the FDI policy more user-friendly, all prior regulations and guidelines have been consolidated into one comprehensive document, which is reviewed every six months. The last review has been released in September 2010. This has been done with the specific intent of enhancing clarity and predictability of our FDI policy to foreign investors. Discussions are underway to further liberalise the FDI policy.

Foreign Institutional Investors

32. Currently, only FIIs and sub-accounts registered with the SEBI and NRIs are allowed to invest in mutual fund schemes. To liberalise the portfolio investment route, it has been decided to permit SEBI registered Mutual Funds to accept subscriptions from foreign investors who meet the KYC requirements for equity schemes. This would enable Indian Mutual Funds to have direct access to foreign investors and widen the class of foreign investors in Indian equity market.

33. To enhance the flow of funds to the infrastructure sector, the FII limit for investment in corporate bonds, with residual maturity of over five years issued by companies in infrastructure sector, is being raised by an additional limit of US Dollar 20 billion taking the limit to US Dollar 25 billion. This will raise the total limit available to the FIIs for investment in corporate bonds to US Dollar 40 billion. Since most of the infrastructure companies are organised in the form of SPVs, FIIs would also be permitted to invest in unlisted bonds with a minimum lock-in period of three years. However, the FIIs will be allowed to trade amongst themselves during the lock-in period.

Financial Sector Legislative Initiatives

34. The financial sector reforms initiated during the early 1990s have borne good results for the Indian economy. The UPA Government is committed to take this process

further. Accordingly, I propose to move the following legislations in the financial sector :

- (i) The Insurance Laws (Amendment) Bill, 2008;
- (ii) The Life Insurance Corporation (Amendment) Bill, 2009;
- (iii) The revised Pension Fund Regulatory and Development Authority Bill, first introduced in 2005;
- (iv) Banking Laws Amendment Bill, 2011;
- (v) Bill on Factoring and Assignment of Receivables;
- (vi) The State Bank of India (Subsidiary Banks Laws) Amendment Bill, 2009; and
- (vii) Bill to amend RDBFI Act, 1993 and SARFAESI Act, 2002.

35. In my last Budget speech, I had announced that Reserve Bank of India would consider giving some additional banking licences to private sector players. Accordingly, RBI issued a discussion paper in August, 2010, inviting feedback from the public. RBI has proposed some amendments in the Banking Regulation Act. I propose to bring suitable legislative amendments in this regard in this session. RBI is planning to issue the guidelines for banking licences before the close of this financial year.

Public Sector Bank Recapitalisation

36. During the year 2010-11, the Government is providing a sum of ₹20,157 crore for infusion in the Public Sector Banks to maintain Tier I Capital to Risk Weighted Asset Ratio (CRAR) at 8 per cent and increase government equity in some banks to 58 per cent. I propose to provide a sum of ₹6,000 crore for the year 2011-12 to enable Public Sector Banks to maintain a minimum Tier I CRAR at 8 per cent.

Recapitalisation of Regional Rural Banks

37. As a part of financial strengthening of Regional Rural Banks, an amount of ₹350 crore was given to these banks during this year. I propose to provide ₹500 crore during 2011-12 to enable them maintain a CRAR of at least 9 per cent as on March 31, 2012.

Micro Finance Institutions

38. The Micro Finance Institutions (MFIs) have emerged as an important means of financial inclusion. Creation of a dedicated fund for providing equity to smaller MFIs would help them maintain growth and achieve scale and efficiency in operations. I propose to create in the course of the year, "India Microfinance Equity Fund" of ₹ 100 crore with SIDBI. To empower women and promote their Self Help Groups (SHGs), I propose to create a "Women's SHG's Development Fund" with a corpus of ₹ 500 crore. The Committee set up by RBI to look into issues relating to micro finance sector in India has submitted its report. The Government is considering putting in place appropriate framework to protect the interests of small borrowers.

Rural Infrastructure Development Fund

39. The Rural Infrastructure Development Fund (RIDF) is an important instrument for routing bank funds for financing rural infrastructure. This is popular among State Governments. I propose to raise the corpus of RIDF XVII to ₹18,000 crore in 2011-12 from ₹16,000 crore in the current year. The additional allocation would be dedicated to creation of warehousing facilities.

Micro, Small and Medium Enterprises

40. Micro and Small enterprises play a crucial role in furthering the objective of equitable and inclusive growth. Last year, ₹4,000 crore was provided to SIDBI for refinancing incremental lending by banks to these enterprises. For the year 2011-12, I propose to provide ₹5,000 crore to SIDBI for the same purpose out of the shortfall of banks on priority sector lending targets.

41. Handloom weavers have been facing economic stress. Consequently, many of them have not been able to repay debts to handloom weaver cooperative societies which have become financially unviable. I propose to provide ₹3,000 crore to NABARD, in phases for these cooperative societies. The initiative would benefit 15,000 cooperative societies and about 3 lakh handloom weavers. The details of the scheme would be worked out by the Ministry of Textiles in consultation with Planning Commission.

42. I am happy to report that the outstanding loans to minority communities which stood at 13 per cent of total priority sector lending at the end of last year have increased to 13.6 per cent in the current year. I have directed the Public Sector Banks to achieve the target of 15 per cent at the earliest.

Housing Sector Finance

43. To further stimulate growth in housing sector, I am liberalising the existing scheme of interest subvention of 1 per cent on housing loans by extending it to housing loan up to ₹ 15 lakh where the cost of the house does not exceed ₹25 lakh from the present limit of ₹10 lakh and ₹20 lakh respectively.

44. On account of increase in prices of residential properties in urban areas, I propose to enhance the existing housing loan limit from ₹ 20 lakh to ₹25 lakh for dwelling units under priority sector lending.

45. To provide housing finance to targeted groups in rural areas at competitive rates, I propose to enhance the provision under Rural Housing Fund to ₹3,000 crore from the existing ₹ 2,000 crore.

46. Credit enablement of Economically Weaker Sections (EWS) and LIG households is a serious challenge. To address this issue, I propose to create a Mortgage Risk Guarantee Fund under Rajiv Awas Yojana. This would guarantee housing loans taken by EWS and LIG households and enhance their creditworthiness.

47. To prevent frauds in loan cases involving multiple lending from different banks on the same immovable property, the Government has facilitated setting up of Central Electronic Registry under the SARFAESI Act, 2002. This Registry will become operational by March 31, 2011.

Financial Sector Legislative Reforms Commission

48. In pursuance of the announcement made in Budget 2010-11, the Government has set up a Financial Sector Legislative Reforms Commission under the Chair of Justice B. N. Srikrishna. It would rewrite and streamline the financial sector laws, rules and regulations and bring them in harmony with the requirements of a modern financial sector. The Commission will complete its work in 24 months.

49. The Companies Bill introduced in the Parliament in 2009 has been received from the Parliamentary Standing Committee. The proposed bill will be introduced in the Lok Sabha in the current session.

Agriculture

50. Agriculture development is central to our growth strategy. Measures taken during the current year have started attracting private investment in agriculture and agro-processing activities. This process has to be deepened further.

51. In the Budget for 2010-11, I had delineated a four-pronged strategy covering agricultural production, reduction in wastage of produce, credit support to farmers and a thrust to the food processing sector. These initiatives have started showing results but there are other issues in our food economy that require attention. The recent spurt in food prices was driven by increase in the prices of items like fruits and vegetables, milk, meat, poultry and fish, which account for more than 70 per cent of the WPI basket for primary food items. Removal of production and distribution bottlenecks for these items will be the focus of my attention this year. I propose to make allocations for these schemes under the ongoing Rashtriya Krishi Vikas Yojana (RKVY) for an early take off. The total allocation of RKVY is being increased from ₹6,755 crore in 2010-11 to ₹7,860 crore in 2011-12.

Bringing Green Revolution to Eastern Region

52. The Green Revolution in Eastern Region is waiting to happen. To realize the potential of the region, last year's initiative will be continued in 2011-12 with a further allocation of ₹400 crore. The program would target the improvement in the rice based cropping system of Assam, West Bengal, Orissa, Bihar, Jharkhand, Eastern Uttar Pradesh and Chhattisgarh.

Integrated Development of 60,000 pulses villages in rainfed areas

53. Government's initiative on pulses has received a positive response from the farmers. As per the second advance estimates, a record production of 165 lakh tonnes of pulses is expected this year as against 147 lakh tonnes last year. While consolidating these gains, we must strive

to attain self-sufficiency in production of pulses within next three years. I propose to provide an amount of ₹300 crore to promote 60,000 pulses villages in rainfed areas for increasing crop productivity and strengthening market linkages.

Promotion of Oil Palm

54. The domestic production of edible oil meets only about 50 per cent demand. The gap in supply is met through imports, which are often at high prices due to the quantum of our requirement. Our recent interventions and good rains are expected to result in a higher oilseeds production of 278 lakh tonnes in 2010-11 as against 249 lakh tonnes in 2009-10. To achieve a major breakthrough, we have to pay special attention to oil palm as it is one of the most efficient oil crops. I propose to provide an amount of ₹300 crore to bring 60,000 hectares under oil palm plantation, by integrating the farmers with the markets. The initiative will yield about 3 lakh metric tonnes of palm oil annually in 5 years.

Initiative on Vegetable Clusters

55. The growing demand for vegetables has to be met by a robust increase in the productivity and market linkage. An efficient supply chain, to provide quality vegetables at competitive prices will have to be established. I propose to provide an amount of ₹300 crore for implementation of vegetable initiative to set in motion a virtuous cycle of higher production and incomes for the farmers. To begin with, this programme will be launched near major urban centres.

Nutri-cereals

56. While we ensure food for all, we must also promote balanced nutrition. Bajra, jowar, ragi and other millets are highly nutritious and are known to possess several medicinal properties. The availability and consumption of these Nutri-cereals is, however, low and has been steadily declining over recent years. A provision of ₹300 crore is being made to promote higher production of these cereals, upgrade their processing technologies and create awareness regarding their health benefits. This initiative would provide market linked production support to ten lakh millet farmers in the arid and semi-arid regions of the country. The programme would be taken up in 1000 compact blocks covering about 25,000 villages. This will help improve nutritional security and increase feed and fodder supply for livestock.

National Mission for Protein Supplements

57. The consumption of foods rich in animal protein and other nutrients has risen of late, with demand growing faster than production. The National Mission for Protein Supplements is being launched in 2011-12 with an allocation of ₹300 crore. It will take up activities to promote animal based protein production through livestock development, dairy farming, piggery, goat rearing and fisheries in selected blocks.

Accelerated Fodder Development Programme

58. Adequate availability of fodder is essential for sustained production of milk. It is necessary to accelerate the production of fodder through intensive promotion of technologies to ensure its availability throughout the year. I propose to provide ₹300 crore for Accelerated Fodder Development Programme which will benefit farmers in 25,000 villages.

59. Hon'ble Members may be curious as to why all these new initiatives are being launched with an allocation of ₹300 crore. Well, the number 3 happens to be my lucky number!

National Mission for Sustainable Agriculture

60. While the need to maximize crop yields to meet the growing demand for food grains is critical, we have to sustain agricultural productivity in the long run. There has been deterioration in soil health due to removal of crop residues and indiscriminate use of chemical fertilizers, aided by distorted prices.

61. To address these issues, the Government proposes to promote organic farming methods, combining modern technology with traditional farming practices like green manuring, biological pest control and weed management.

Agriculture Credit

62. To get the best from their land, farmers need access to affordable credit. Banks have been consistently meeting the targets set for agriculture credit flow in the past few years. For the year 2011-12, I am raising the target of credit flow to the farmers from ₹3,75,000 crore this year to ₹4,75,000 crore in 2011-12. Banks have been asked to step up direct lending for agriculture and credit to small and marginal farmers.

63. The existing interest subvention scheme of providing short-term crop loans to farmers at 7 per cent interest will be continued during 2011-12. In the last budget, I had provided an additional 2 per cent interest subvention to those farmers who repay their crop loans on time. The response to this scheme has been good. In order to provide further incentive to these farmers, I propose to enhance the additional subvention to 3 per cent in 2011-12. Thus, the effective rate of interest for such farmers will be 4 per cent per annum.

64. In view of the enhanced target for flow of agriculture credit, I propose to strengthen NABARD's capital base by infusing ₹3000 crore, in a phased manner, as Government equity. This would raise its paid-up capital to ₹5,000 crore. To enable NABARD refinance the short-term crop loans of the cooperative credit institutions and RRBs at concessional rates, I propose a contribution of ₹10,000 crore to NABARD's Short-term Rural Credit Fund for 2011-12 from the shortfall in priority sector lending by Scheduled Commercial Banks.

Mega Food Parks

65. Despite growing production of vegetables and fruits, their availability is inadequate due to bottlenecks in retailing capacity. An estimated 40 per cent of the fruit and vegetable production in India goes waste due to lack of storage, cold chain and transport infrastructure. To address these issues, the Eleventh Plan target for number of Mega Food Parks was set at 30. So far, 15 such parks have been sanctioned. During 2011-12, approval is being given to set up 15 more Mega Food Parks.

Storage Capacity and Cold Chains

66. The years 2008 to 2010 saw very high levels of foodgrain procurement. On January 1, 2011, the food grain stock in Central pool reached 470 lakh metric tonnes, 2.7 times higher than 174 lakh metric tonnes on January 1, 2007. The storage capacity for such large quantities requires augmentation. Process to create new storage capacity of 150 lakh metric tonnes through private entrepreneurs and warehousing corporations has been fast tracked. Decision to create 20 lakh metric tonnes of storage capacity under Public Entrepreneurs Guarantee (PEG) Scheme through modern silos has been taken. While we will be able to add about 2.6 lakh tonnes of capacity by March 2011, based on existing sanctions, the addition will reach 40 lakh tonnes by March 2012. During 2010-11, another 24 lakh metric tonnes of storage capacity has been created under the Rural Godown Scheme.

67. Investment in cold storage projects is now gaining momentum. During this year, 24 cold storage projects with a capacity of 1.4 lakh metric tonnes have been sanctioned under National Horticulture Mission. In addition, 107 cold storage projects with a capacity of over 5 lakh metric tonnes have been approved by the National Horticulture Board.

68. To attract investment in this sector, henceforth, capital investment in the creation of modern storage capacity will be eligible for viability gap funding scheme of the Finance Ministry. It is also proposed to recognize cold chains and post-harvest storage as an infrastructure sub-sector.

Agriculture Produce Marketing Act

69. The recent episode of inflation in vegetables and fruits has exposed serious flaws in our supply chains. The government regulated mandis sometimes prevent retailers from integrating their enterprises with the farmers. There is need for the State Governments to review and enforce a reformed Agriculture Produce Marketing Act urgently.

Infrastructure and Industry

70. Infrastructure is critical for our development. For 2011-12, an allocation of over ₹2,14,000 crore is being made for this sector, which is 23.3 per cent higher than Current year. This amounts to 48.5 per cent of the Gross Budgetary Support to plan expenditure.

71. Our experience with PPP model for creation of public sector assets in the country has been good. We have recently launched the National Capacity Building

Programme to enhance capacities of public functionaries in identifying, conceptualising, structuring and managing PPPs. It is our endeavour to come up with a comprehensive policy that can be used by the Centre and the State Governments in further developing public-private partnerships.

72. Government established India Infrastructure Finance Company Limited (IIFCL) to provide long term financial assistance to infrastructure projects. It is expected to achieve a cumulative disbursement target of ₹20,000 crore by March 31, 2011 and ₹25,000 crore by March 31, 2012. The take out financing scheme announced in the Budget 2009-10 has been implemented and seven projects have been sanctioned with a debt of ₹ 1,500 crore. Another ₹5,000 crore will be sanctioned during 2011-12.

73. In order to give a boost to infrastructure development in railways, ports, housing and highways development, I propose to allow tax free bonds of ₹30,000 crore to be issued by various Government undertakings in the year 2011-12. This includes Indian Railway Finance Corporation ₹10,000 crore, National Highway Authority of India ₹10,000 crore, HUDCO ₹5,000 crore and Ports ₹5,000 crore.

74. To attract foreign funds for the infrastructure financing, I propose to create Special Vehicles in the form of notified infrastructure debt funds. I will come to the details in Part B of my speech.

National Manufacturing Policy

75. For sustained growth of GDP and productive employment for younger generation, it is imperative that the growth in manufacturing sector picks up. We expect to take the share of manufacturing in GDP from about 16 per cent to 25 per cent over a period of ten years. Government will come out with a manufacturing policy, which will bring down the compliance burden on the industry through self-regulation and help make Indian industry globally competitive.

76. To address the need for greater transparency and accountability in procurement policy and allocation, pricing and utilisation of natural resources, the Government has set up two committees. The recommendations will be available within three months.

77. A Group of Ministers has been set up to consider all issues relating to reconciliation of environmental concerns emanating from various departmental activities including those related to infrastructure and mining. This Group will also suggest changes in the existing statutes, rules, regulations and guidelines and make its recommendations in a time bound manner.

78. The Indian automobile market is the second fastest growing in the world and has shown nearly 30 per cent growth this year. World over, substantial investments are being made in the field of hybrid and electric mobility. To provide green and clean transportation for the masses, National Mission for Hybrid and Electric Vehicles will be launched in collaboration with all stakeholders.

79. The funding of 15,260 modern low floor and semi-low floor buses under JNNURM, besides adding to passenger comfort, has transformed the urban transport across India. In 2011-12, Delhi Metro Phase-III and Mumbai Metro Line III are proposed to be taken up. The ongoing Metro projects of Bengaluru, Kolkata and Chennai will be provided financial assistance for speedy implementation.

80. Investment in fertilizer sector is capital intensive and is considered high risk. It is proposed to include capital investment in fertiliser production as an infrastructure sub-sector.

Exports

81. The Task Force on Transactions Cost set up by the Department of Commerce to identify and suggest ways to achieve improvement in efficiency of our export processes, has completed its work. Twenty one suggestions made by the Task Force have already been implemented. Action on remaining two will be taken in next few months. This will mitigate transactions cost by about ₹2,100 crore.

82. To quicken the clearance of the cargo by Customs authorities and further modernise the Customs administration, I propose to introduce self-assessment in Customs. Under this, importers and exporters will themselves assess their duty liabilities while filing their declarations in the EDI system. The Department will verify such assessments on a selective system driven basis.

83. There have been considerable difficulties in the sanction of refunds relating to tax paid on services used for export of goods. I propose to shortly introduce a scheme for the refund of these taxes on the lines of drawback of duties in a far more simplified and expeditious manner. A new scheme is also being introduced by which units in SEZs will be able to obtain tax-free receipt of services wholly consumed within the zone and get their refunds in a much easier manner.

84. Mega clusters have large employment and export potential. I propose to extend the Mega Cluster Scheme for development of leather products. Seven mega leather clusters would be set up during the year 2011-12. I also propose to include Jodhpur for the development of a handicraft mega cluster.

Black Money

85. The generation and circulation of black money is an area of serious concern. To deal with this problem effectively, Government has put into operation a five-fold strategy which consists of Joining the global crusade against 'black money'; Creating an appropriate legislative framework; Setting up institutions for dealing with illicit funds; Developing systems for implementation; and Imparting skills to the manpower for effective action.

86. We secured Membership of the Financial Action Task Force (FATF) in June last year. This is an important initiative of G-20 for anti-money laundering. We have also joined the Task Force on Financial Integrity and Economic Development, Eurasian Group (EAG) and Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes.

748 9711-4

87. During the year, we have concluded discussions for 11 Tax Information Exchange Agreements (TIEAs) and 13 new Double Taxation Avoidance Agreements (DTAAs) along with revision of provisions of 10 existing DTAAs. To effectively handle the increase in tax information exchange and transfer pricing issues, Foreign Tax Division of CBDT has been strengthened. A dedicated Cell for exchange of information is being set up to work on this agenda.

88. The amendment in our Money Laundering Legislation in 2009 has significantly increased its scope and application. The number of cases registered under this law has increased from 50 between 2005 to 2008 to over 1200 by January this year. The strength of the Enforcement Directorate has been increased three-fold to deal effectively with the increased workload.

89. The Ministry of Finance has commissioned a study on unaccounted income and wealth held within and outside our country. It would suggest methods to tax and repatriate this illicit money.

90. Trafficking in narcotic drugs is also a contributor to the generation of black money. To strengthen controls over prevention of trafficking and improve the management of narcotic drugs and psychotropic substances, I propose to announce a comprehensive national policy in the near future.

III. Strengthening Inclusion

91. The UPA Government has engineered a major directional change in public policy by its focus on inclusive development. Creation of legal entitlements for an individual's right to work has added to resilience and dynamism in our rural economy. The right to information and the right to education are effective tools of empowerment for removing social imbalances. The country has carried for long enough the burden of hunger and malnutrition. After detailed consultations with all stakeholders including State Governments, we are close to the finalisation of National Food Security Bill (NFSB) which will be introduced in the Parliament during the course of this year. The proposed allocation of ₹1,60,887 crore for social sector in 2011-12 is an increase of 17 per cent over current year. It amounts to 36.4 per cent of the total plan allocation.

Bharat Nirman

92. The UPA Government's flagship programmes have been the principal instrument for implementing its agenda for inclusive development. For the year 2011-12, Bharat Nirman, which includes Pradhan Mantri Gram Sadak Yojna (PMGSY), Accelerated Irrigation Benefit Programme, Rajiv Gandhi Grameen Vidyutikaran Yojna, Indira Awas Yojna, National Rural Drinking Water Programme and Rural Telephony have together been allocated ₹58,000 crore. This is an increase of ₹10,000 crore from the current year. A plan has been finalised to provide Rural Broadband Connectivity to all 2,50,000 Panchayats in the country in three years.

MGNREGA

93. In pursuance of my earlier budget announcement to provide a real wage of ₹100 per day, the Government has decided to index the wage rates notified under the MGNREGA to the Consumer Price Index for Agricultural Labour. The enhanced wage rates have been notified by the Ministry of Rural Development on January 14, 2011. It has resulted in significant enhancement of wages for the beneficiaries across the country.

94. The Anganwadi workers and Anganwadi helpers are the backbone of Integrated Child Development Services Scheme. I am happy to announce an increase in the remuneration of Anganwadi workers from ₹1,500 per month to ₹3,000 per month and for Anganwadi helpers from ₹750 per month to ₹1,500 per month. This will be effective from April 1, 2011. Around 22 lakh Anganwadi workers and helpers will benefit from the increase.

Scheduled Castes and Tribal Sub-plan

95. In the Budget for 2011-12, for the first time, specific allocations are being earmarked towards Scheduled Castes Sub-plan and Tribal Sub-plan. These will be shown in the Budget of the relevant Ministries and Departments under separate minor heads of account. Further, I propose to increase the Budget allocation for primitive tribal groups from ₹185 crore in 2010-11 to ₹244 crore in 2011-12.

Education

96. Our "demographic dividend" of a relatively younger population compared to developed countries is as much of an opportunity as it is a challenge. Over 70 per cent of Indians will be of working age in 2025. In this context, universalising access to secondary education, increasing the percentage of our scholars in higher education and providing skill training is necessary. For education, I propose an allocation of ₹52,057 crore, which is an increase of 24 per cent over the current year.

Sarva Shiksha Abhiyan

97. The existing operational norms of Sarva Shiksha Abhiyan have been revised to implement the right of children to free and compulsory education which has come into force with effect from April 1, 2010. For the year 2011-12, I propose to allocate ₹21,000 crore which is 40 per cent higher than ₹15,000 crore allocated in the Budget for 2010-11. A revised Centrally Sponsored Scheme "Vocationalisation of Secondary Education" will be implemented from 2011-12 to improve the employability of our youth.

98. Empowerment flows from Education. While the Scheduled Castes and Scheduled Tribes had access to post matric scholarships, there was so far a lack of pre-matric scholarship scheme. In 2011-12, I propose to introduce a scholarship scheme for needy students belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes studying in classes ninth and tenth. It would benefit about 40 lakh Scheduled Caste and Scheduled Tribe students.

National Knowledge Network

99. Approved in March 2010, the National Knowledge Network (NKN) will link 1500 Institutes of Higher Learning and Research through an optical fibre backbone. During the current year, 190 Institutes will be connected to NKN. Since the core will be ready by March 2011, the connectivity to all 1500 institutions will be provided by March 2012.

Innovations

100. To move beyond the formal R&D paradigm, a National Innovation Council under Shri Sam Pitroda has been set up to prepare a roadmap for innovations in India. The process of setting up State Innovation Councils in each State and Sectoral Innovation Councils aligned to Central Ministries is underway.

101. The Government has been providing special grants to recognise excellence in universities and academic institutions. In the course of 2011-12, I propose to provide:

- ₹50 crore each to upcoming centres of Aligarh Muslim University at Murshidabad in West Bengal and Malappuram in Kerala;
- ₹100 crore as one-time grant to the Kerala Veterinary and Animal Sciences University at Pookode, Kerala;
- ₹10 crore each for setting up Kolkata and Allahabad Centres of Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya, Wardha;
- ₹200 crore as one time grant to IIT, Kharagpur;
- ₹20 crore for Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development, Sriperumbudur, Tamil Nadu;
- ₹20 crore for IIM, Kolkata, to set up its Financial Research and Trading Laboratory;
- ₹200 crore for Maulana Azad Education Foundation;
- ₹10 crore for Centre for Development Economics and Ratan Tata Library, Delhi School of Economics, Delhi; and
- ₹10 crore for Madras School of Economics.

Skill Development

102. I am happy to inform the House that National Skill Development Council (NSDC) is well on course to achieve its mandate of creation of 15 crore skilled workforce two years ahead of 2022, the stipulated target year. It has already sanctioned 26 projects with a total funding of ₹658 crore. These projects alone are expected to create more than 4 crore skilled workforce over the next ten years. In the current year, skill training has so far been provided to 20,000 persons. Of these, 75 per cent have found placements. I will provide an additional ₹500 crore to the National Skill Development Fund during the next year.

103. National celebrations of 150th Birth Anniversary of Gurudev Rabindranath Tagore will commence from May 7

2011 in New Delhi. Important events will be held in several countries in Europe, America and Asia. A series of events are also proposed to be organized under the aegis of joint India-Bangladesh Celebrations Committee. An international award with prize money of ₹1 crore is being instituted for promoting values of Universal Brotherhood in the memory of Gurudev Rabindranath Tagore.

Health

104. For health, I propose to set up the plan allocations in 2011-12 by 20 per cent to ₹26,760 crore. The Rashtriya Swasthya Bima Yojana has emerged as an effective instrument for providing a basic health cover to poor and marginal workers. It is now being extended to MGNREGA beneficiaries, beedi workers and others. In 2011-12, I propose to further extend this scheme to cover unorganized sector workers in hazardous mining and associated industries like slate and slate pencil, dolomite, mica and asbestos etc.

Financial Inclusion

105. In my last budget speech I had advised Banks to provide banking facilities to habitations having a population of over 2000 by March, 2012. The Banks have identified about 73,000 such habitations for providing banking facilities using appropriate technologies. A multi-media campaign, "Swabhimaan", has been launched to inform, educate and motivate people to open bank accounts. During this year, banks will cover 20,000 villages. Remaining will be covered during 2011-12.

Unorganised sector

106. I had announced a co-contributory pension scheme "Swavalamban" in the Budget 2010-11. This scheme has been welcomed by the workers in unorganised sector. Over 4 lakh applications have already been received. On the basis of the feedback received, I am relaxing the exit norms whereby a subscriber under Swavalamban will be allowed exit at the age of 50 years instead of 60 years, or a minimum tenure of 20 years, whichever is later. I also propose to extend the benefit of Government contribution from three to five years for all subscribers of Swavalamban who enroll during 2010-11 and 2011-12. An estimated 20 lakh beneficiaries will join the scheme by March 2012.

107. Under the on-going Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme for BPL beneficiaries, the eligibility for pension is proposed to be reduced from 65 years at present to 60 years. Further, for those who are 80 years and above, the pension amount is being raised from ₹200 at present to ₹500 per month.

Environment and Climate Change Forests

108. Protection and regeneration of forests has great ecological, economic and social value. Our Government has launched an ambitious ten-year Green India mission. I propose to allocate ₹200 crore from the National Clean Energy Fund to begin its implementation in 2011-12.

Environmental Management

109. Environmental pollution has emerged as a serious public health concern across the country. I propose to allocate ₹200 crore from the National Clean Energy Fund as Centre's contribution in 2011-12 for launching environmental remediation programmes.

Cleaning of Rivers and Lakes

110. A number of projects under the National Ganga River Basin Authority have been approved in 2010-11. This momentum will be further stepped up. There are many rivers and lakes of cultural and historical significance that need to be cleaned. In the course of the year 2011-12, I propose to provide a special allocation of ₹200 crore for the clean-up of some important lakes and rivers other than the Ganga.

Some Other Initiatives

111. In order to boost development in the North Eastern Region and Special Category States, the allocation for special assistance has been almost doubled to 8,000 crore for 2011-12. Out of this, ₹5,400 crore has been allocated as untied Special Central Assistance.

112. The Government's special support to Jammu & Kashmir is anchored in ₹28,000 crore Prime Minister's Reconstruction Plan. In addition, for the Current year, about ₹8,000 crore has been provided for the State's development needs. A Task Force to assess infrastructure needs that can be addressed within a time horizon of 24 months for Ladakh and Jammu regions of the State has recommended projects amounting to ₹416 crore and ₹497 crore, respectively. I am providing ₹100 crore for Ladakh and ₹150 crore for Jammu for these identified projects in 2011-12.

113. To give a boost to the development of backward regions, the allocation under the Backward Regions Grant Fund has been increased from ₹7,300 crore to ₹9,890 crore amounting to an increase of over 35 per cent.

114. To address problems related to Left Wing Extremism affected districts, an Integrated Action Plan (IAP) for 60 selected tribal and backward districts has been launched in December 2010. The scheme is being implemented with 100 per cent block grant of ₹25 crore and ₹30 crore per district during the years 2010-11 and 2011-12, respectively. The allocated funds are placed at the disposal of the district level committees who in consultation with local MPs will have the flexibility to spend the amount on development schemes as per the local needs.

115. In recognition of the sacrifices made by Central Para-military Forces engaged in tackling Left Wing Extremism, a lump sum ex-gratia compensation of ₹9 lakh for 100 per cent disability will now be granted to personnel of the Defence and para-military forces who are discharged from service on medical grounds on account of disability

attributable to or aggravated in government service. For personnel with disability ranging from 20 to 99 per cent, a proportionate amount would be given.

116. In the Budget 2011-12, a provision of ₹1,64,415 crore has been made for Defence services which include ₹69,199 crore for capital expenditure. Needless to say, any further requirement for the country's defence would be met.

117. In order to speed up delivery of justice, the Plan provision for Department of Justice for 2011-12 has been increased three-fold to ₹1,000 crore. The enhanced provision will help in building judicial infrastructure and the project on E-courts.

Census 2011

118. The 15th Census in the country is being conducted from 9th February. It is the largest administrative exercise in the country providing statistical data on different socio-economic parameters of population.

119. In response to the overwhelming demand for enumeration of castes other than Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Census 2011, it has been decided to canvass 'caste' as a separate time bound exercise. This exercise will start in June 2011 and will be completed by 30th September, 2011.

IV. Improving Governance

I now turn to some important measures being taken for improving governance.

UID Mission

120. The UID Mission has taken off and Aadhaar numbers are being generated in large numbers. So far 20 lakh Aadhaar numbers have been given and from 1st October 2011, ten lakh numbers will be generated per day. The stage is now set for realising the potential of Aadhaar for improving service delivery, accountability and transparency in governance of various schemes.

IT Initiatives

121. The backbone of an efficient tax administration is a robust IT infrastructure and its deployment for enhanced taxpayer services. Towards this objective, both the Central Boards of Direct Taxes (CBDT) and Excise and Customs (CBEC) have put in place the following measures:

- The on-line preparation and e-filing of income tax returns, e-payment of taxes through 32 agency banks, ECS facility for electronic clearing of refunds directly in taxpayers' bank accounts and electronic filing of TDS returns are now available throughout the country. These measures have empowered taxpayers to meet their tax obligations without visiting an income tax office.
- The Centralized Processing Centre (CPC) at Bengaluru has increased its daily processing capacity from 20,000 to 1.5 lakh returns in

2010-11. This project has won a Gold Award for e-Governance in 2011. Two more CPCs will become operational in Manesar and Pune by May 2011 and a fourth CPC will come up in Kolkata in 2011-12.

- With the completion of its IT Consolidation Project, CBEC can now centrally host its key applications in Customs, Central Excise and Service Tax. The Customs EDI system now covers 92 locations across the country. CBEC's e-Commerce portal ICEGATE, has also been conferred a Gold Award for e-Governance.
- The 'Sevottam' concept has been adopted by both Boards. The three pilot projects of Aaykar Seva Kendras (ASKs) under CBDT have come of age. CBDT will commission eight more such centres this year. In 2011-12, another fifty ASKs will be set up across the country. CBEC has also launched a similar initiative and four of their pilot projects have been commissioned.
- The electronic filing of Tax Deduction at Source (TDS) statements has stabilized. The Board shall soon notify a category of salaried taxpayers who will not be required to file a return of income as their tax liability has been discharged by their employer through deduction at source.
- CBDT will provide a separate web-based facility to enable a direct, stand-alone interface for taxpayers with the Income Tax Department so that they can report and track the resolution of their refunds and credit for prepaid taxes.

122. Mission Mode Projects for computerisation of Commercial Taxes in States that I announced in my last Budget, will allow States to align with the roll out of GST. Funds have been released for 31 projects received from the States and Union Territories. Most of the States and UTs have already enabled the facility of dealers making electronic payments. A number of States have already started accepting Electronic Tax Returns and issuing forms required for inter-state trade.

123. With the development of the economy, the need to review the provisions of the Indian Stamp Act, 1899 has been felt over the years. I propose to introduce a Bill shortly to amend the Indian Stamp Act.

124. Five years ago, we took an initiative to introduce a modern and people-friendly e-stamping facility in the country. Only six States have introduced this system so far. I propose to launch a new scheme with an outlay of ₹ 300 crore to provide assistance to States to modernise their stamp and registration administration and roll out e-stamping in all the districts in the next three years.

125. I propose to introduce a new simplified return form 'Sugam' to reduce the compliance burden of small taxpayers who fall within the scope of presumptive taxation.

126. The increase in scope of cases admitted by the Settlement Commissions has provided relief to several taxpayers. This has also increased the workload of the Commission. To fast track the disposal of cases, three more Benches of the Commission are being set up.

127. Substantial amounts of revenue in both direct and indirect taxes, remain locked up in appeals at different levels. Both Boards also invest substantial effort and money in litigation with their employees. In keeping with the National Litigation Policy, several steps have been initiated in 2010-11 for reducing litigation and focusing attention on high revenue cases. Instructions have been issued raising limit of tax effects below which, tax disputes will not be pursued by Government in higher Courts of Appeal. These measures would enhance productivity of resources employed in raising revenue.

Corruption

128. A Group of Ministers has been constituted to consider measures for tackling corruption. The Group has been tasked with addressing issues relating to State funding of elections, speedier processing of corruption cases of public servants, transparency in public procurement and contracts, discretionary powers of Central ministers and competitive system for exploiting natural resources. The Group will make its recommendations in a time bound manner.

Performance Monitoring and Evaluation System

129. Pursuant to the recommendations of Second Administrative Reforms Commission, the Government has set up a Performance Monitoring and Evaluation System (PMES) to assess the effectiveness of Government departments in their mandated functions. It involves preparation of a Results Framework Document (RFD) by each department, highlighting its objectives and priorities for the financial year and achievements against pre-specified targets at the end of the year. This document would be available for public information on the departmental websites. In the first phase, 62 departments have been covered under PMES.

TAGUP

130. In pursuance of the announcement made in the Budget 2010-11, I had set up a Technology Advisory Group for Unique Projects (TAGUP). The Group has submitted its report and its recommendations have been accepted in principle. The modalities of implementation are being worked out.

131. Indian Rupee now has a new symbol which has been notified for use by the Central and State Governments, business entities and the general public. A new series of coins carrying this symbol will be issued shortly. The Government has approached Unicode Standards Authority for inclusion of the symbol in international standards.

V. Budget Estimates 2011-12

I now turn to the Budget Estimates for 2011-12.

132. The Gross Tax Receipts are estimated at ₹9,32,440 crore which is an increase of 24.9 per cent over the Budget Estimates for 2010-11. After devolution to States, the net tax to Centre in 2011-12 is ₹6,64,457 crore. The Non Tax Revenue Receipts for 2011-12 are estimated at ₹1,25,435 crore.

133. The total expenditure proposed for 2011-12 is ₹12,57,729 crore, which is an increase of 13.4 per cent over the Budget Estimates for 2010-11. The Plan Expenditure at ₹4,41,547 crore marks an increase of 18.3 per cent and the Non Plan Expenditure at ₹8,16,182 crore is an increase of 10.9 per cent over BE 2010-11. As 2011-12 is the last year of the Eleventh Plan, I am happy to share that Eleventh Plan expenditure in nominal terms is more than 100 per cent of the expenditure envisaged for the Plan period.

134. The total plan and non-plan transfers of ₹2,01,733 crore to States and UT Governments in 2011-12 have increased by 23 per cent over the Budget Estimates 2010-11. This includes grants of ₹13,713 crore in 2011-12 to local bodies as per the recommendation of the Thirteenth Finance Commission.

135. Hon'ble Members are aware that in the course of 2010-11, I had the opportunity to effect a further improvement in the fiscal balance, due to the higher than anticipated non-tax revenues from 3G spectrum auctions. I choose to do that and much more. While I provided additional resources of about ₹50,000 crore to critical infrastructure and social sectors and also to meet the expenditure on subsidies, I have brought down the fiscal deficit from 5.5 per cent to 5.1 per cent of the GDP for 2010-11. For 2011-12, I have kept it at 4.6 per cent of GDP, which improves upon my own target for 2011-12 indicated in the fiscal road map presented in the last Budget. In the Medium Term Fiscal Policy Statement being presented to the House today, the rolling targets for fiscal deficit are placed at 4.1 per cent for 2012-13, and 3.5 per cent for 2013-14.

136. There has been some concern expressed regarding the stickiness of Government's revenue deficit in the post-global crisis phase of the economy. For 2010-11 as against a target of 4 per cent, the revenue deficit is estimated at 3.4 per cent of GDP. In the past few years the transfers to States and other developmental expenditure have grown significantly. These are classified as revenue expenditure even though a considerable part of the expenditure from these transfers is in the nature of capital expenditure. In 2010-11, ₹90,792 crore from such revenue expenditures were in the nature of capital expenditure. Similarly, in 2011-12 grants-in-aid for creation of capital assets, which are now shown separately in the Budget documents, are about ₹1.47 lakh crore. Taking these budget provisions into account, the "effective revenue deficit" is estimated at 2.3 per cent in the Revised Estimates for 2010-11 and 1.8 per cent for 2011-12.

137. In my last Budget, I had stated that Government would avoid issuing bonds in lieu of subsidies to oil and fertiliser companies. I have adhered to this decision, thereby bringing all subsidy related liabilities into our fiscal accounting.

138. The fiscal deficit of 4.6 per cent of GDP in 2011-12 works out to ₹4,12,817 crore. Taking into account the various other financing items for fiscal deficit, the net market borrowing of the Government in 2011-12 would be ₹3.43 lakh crore. In addition, ₹15,000 crore is proposed to be financed through Treasury Bills. Accordingly, the Central Government debt as a proportion of GDP is estimated at 44.2 per cent for 2011-12 as against 52.5 per cent recommended by the Thirteenth Finance Commission.

PART - B

Madam Speaker,

I shall now present my tax proposals.

139. In the formulation of these proposals, my priorities are directed towards making taxes moderate, payments simple for the taxpayer and collection of taxes easy for the tax collector.

VI. Direct Taxes

I shall now deal with direct taxes.

140. As Government's policy on direct taxes has been outlined in the DTC, which is before Parliament, I have limited my proposals to initiatives that require urgent attention.

141. Last year I provided relief to individual taxpayers by broadening the tax slabs. To take us closer to DTC rates, I propose to enhance the exemption limit for the general category of individual taxpayers from ₹1,60,000 to ₹1,80,000 this year. This measure will provide a uniform tax relief of ₹2,000 to every taxpayer of this category.

142. Senior citizens deserve our special attention. For them, I propose.

- to reduce the qualifying age, from 65 years to 60 years;
- to enhance the exemption limit from ₹2,40,000 to ₹2,50,000;
- To create a new category of Very Senior Citizens, eighty years and above, who will be eligible for a higher exemption limit of ₹5,00,000.

143. In the case of corporates, my initiative of phasing out the surcharge continues. I propose to reduce the current surcharge of 7.5 per cent on domestic companies to 5 per cent. Simultaneously I propose to increase the rate of Minimum Alternate Tax (MAT) from the current rate of 18 per cent to 18.5 per cent of book profits to keep the effective rate of the MAT at the same level. As a measure to ensure equal sharing of the corporate tax liability, I propose to levy MAT on developers of Special Economic Zones as well as units operating in SEZs.

144. To attract foreign funds for financing of infrastructure, I propose to :

- create special vehicles in the form of notified infrastructure debt funds;
- subject interest payment on the borrowings of these funds to a reduced withholding tax rate of 5 per cent instead of the current rate of 20 per cent;
- exempt the income of the fund from tax.

145. In order to promote savings and raise funds for infrastructure, an additional deduction of ₹20,000 for investment in long-term infrastructure bonds was notified by the Central Government in 2010-11. I propose to extend this window for one more year.

146. It has been represented that the taxation of foreign dividends in the hands of resident taxpayers at full rate is a disincentive for their repatriation to India and they continue to remain invested abroad. For the year 2011-12, I propose a lower rate of 15 per cent tax on dividends received by an Indian company from its foreign subsidiary. I do hope these funds will now flow to India.

147. In order to give a boost to production in the agriculture sector, I propose to extend the benefit of investment linked deduction to businesses engaged in the production of fertilisers.

148. Considering the importance of housing, I also propose investment linked deduction to businesses which develop affordable housing under a notified scheme.

149. In this Decade of Innovation, I enhanced the weighted deduction on payments made to National Laboratories, Universities and Institutes of Technology, for scientific research, to 175 per cent in the last budget. I propose to further enhance this to 200 per cent.

150. In order to strengthen our system of collection of information from foreign tax jurisdictions, I propose to provide a toolbox of counter measures to discourage transactions with entities located in non-cooperative jurisdictions as may be notified by the Government.

151. My proposals on direct taxes are estimated to result in a net revenue loss of ₹11,500 crore for the year.

VII. Indirect Taxes

I shall now turn to my indirect tax proposals.

152. In view of the healthy growth in indirect taxes in 2010-11, I had the option to roll back the Central Excise duty to levels prevailing in November, 2008. I have chosen not to do so for two reasons. I would like to see improved business margins translated into higher investment rates. I would also like to stay my course towards GST. I have therefore decided to maintain the standard rate of Central Excise duty at 10 per cent.

153. I propose certain changes in the Central Excise rate structure to prepare the ground for the transition to GST, beginning with a reduction in the number of exemptions. At present, there are about 100 items that are

exempt from Central Excise as well as State VAT. In addition, there are as many as 370 items that enjoy exemption from Central Excise duty but are chargeable to VAT. I propose to withdraw the exemption on 130 of these items that are mainly in the nature of consumer goods. The remaining 240 items would be brought into the tax net when GST is introduced.

154. A nominal Central Excise duty of 1 per cent is being imposed on the 130 items that are entering the tax net. No Cenvat credit would be available for the manufacture of these items. Basic food and fuel would continue to be exempt. This levy would also not apply to precious metals and stones. In case of jewellery and articles of gold, silver and precious metals, the levy would apply only to goods sold under a brand name.

155. Most of the States have increased their merit rate of VAT from 4 per cent to 5 per cent. In line with this, I also propose to enhance the lower rate of Central Excise duty from 4 per cent to 5 per cent.

156. Ready-made garments and made-ups of textiles are currently under an optional excise duty regime. A manufacturer is required to pay duty only if he wishes to avail of Cenvat credit. Our garment and made-ups industry has come of age and has shown handsome growth in recent years. As part of base expansion, I propose to convert the optional levy into a mandatory levy at a unified rate of 10 per cent. The levy would however, apply only to branded garments or made-ups and not to those tailored or made to order for a retail customer. Credit of tax paid on inputs, capital goods and input services would be available to manufacturers of these products. Keeping in mind the fragmented nature of this industry, full SSI exemption is also being extended to these products. Export of these items would continue to be zero-rated.

157. We have a long term commitment to align our customs duty rates to those prevailing in ASEAN countries. The peak rate of customs duty has been reduced over the years and has settled at 10 per cent. In view of continued uncertainties in the global economy, I propose to hold the peak rate at its current level. However, some rationalization is being done to unify three rates namely, 2 per cent, 2.5 per cent and 3 per cent at the middle level of 2.5 per cent.

158. I now turn to proposals that are aimed at encouraging some of the thrust sectors that are in need of attention.

Agriculture and Related Sectors

159. Hon'ble Members would recall that, in the last Budget, I had announced a package of measures to improve the availability of storage and warehouse facilities for agricultural produce as well as to incentivize food processing. I have received encouraging feedback on the impact of these measures. I propose to enlarge the scope of these exemptions by :

- extending full exemption from excise duty to air-conditioning equipment and refrigeration panels for cold chain infrastructure;

- including conveyor belts in the full exemption from excise duty to equipment used in cold storages, mandis and warehouses.

160. A concessional rate of basic customs duty of 5 per cent was provided to specified agricultural machinery in the last budget. This duty is being reduced further to 2.5 per cent and the concession is also being extended to parts of such machinery to encourage their domestic production.

161. Micro-irrigation is an environment-friendly and efficient means of irrigation especially for dry land farming. I propose to reduce the basic customs duty on micro-irrigation equipment from 7.5 per cent to 5 per cent.

162. De-oiled rice bran cake constitutes an important ingredient of cattle feed and its improved availability would have a positive impact on milk production. I propose to provide full exemption from basic customs duty to this item. Simultaneously, an export duty of 10 per cent would be levied to discourage its export.

Manufacturing Sector

163. For the manufacturing sector, my proposals seek to encourage domestic value addition vis-a-vis imports, to remove duty inversions and anomalies and to provide a level playing field to the domestic industry. The major proposals are to :

- reduce basic customs duty on raw silk (not thrown) from 30 to 5 per cent;
- reduce basic customs duty from 5 per cent to 2.5 per cent on certain textile intermediates and inputs for chemicals, ferro-alloys and paper;
- reduce basic customs duty on certain specified inputs for manufacture of certain technical fibre and yarn from 7.5 per cent to 5 per cent;
- fully exempt stainless steel scrap from basic customs duty;
- reduce import duties on specified raw material for the manufacture of syringes and needles to 5 per cent basic and 4 per cent CVD;
- extend the concession available to parts, components and accessories for manufacture of mobile handsets till 31st March, 2012 and to include few more items in its ambit;
- expand the raw material list for manufacture of specified electronic components that are fully exempt from basic customs duty;
- reduce excise duty (and hence CVD) on parts of ink-jet and laser-jet printers from 10 per cent to 5 per cent.

164. Iron ore attracts an export duty of 15 per cent in the case of lumps and 5 per cent in the case of fines. This is a natural resource which needs to be conserved. I propose to enhance the rate of export duty for all types of iron ore and unify it at 20 per cent ad valorem. Iron ore is also exported in a value-added, pelletized form. Full exemption

from export duty is being provided to iron ore pellets to encourage the value addition process for fines.

165. As a measure of relief to cement industry, I propose to replace the existing excise duty rates with composite rates having an ad valorem and specific component with some rationalization. The basic customs duty on two critical raw materials of this industry viz. petcoke and gypsum is proposed to be reduced to 2.5 per cent.

166. To drive the financial inclusion agenda of the Government, I propose to fully exempt cash dispensers from basic customs duty. Full exemption is also being extended to parts of such machines to encourage their domestic production.

Environment

167. Full exemption from basic customs duty and a concessional rate of Central Excise duty of 4 per cent was provided to specified parts of electrical vehicles in the last Budget on actual-user basis. I propose to extend the concession to batteries imported by such manufacturers for the replacement market.

168. Fuel cell or Hydrogen cell technology is a promising green technology for the automobile sector. I propose to extend the concessional excise duty of 10 per cent to vehicles based on this technology.

169. Hybrid vehicles enjoy a concessional excise duty rate of 10 per cent. However, import dependence for their critical parts/sub-assemblies is still quite high. It is proposed to grant specified parts of such vehicles full exemption from basic customs duty and special CVD. In addition, a concessional rate of excise duty of 5 per cent is being prescribed to incentivise their domestic production.

170. In response to the growing demand for green products, a technology has been developed indigenously for the conversion of fossil fuel vehicles into Hybrid vehicles through the fitment of a kit. I propose to reduce the excise duty on such kits and their parts from 10 per cent to 5 per cent.

171. In the last Budget, Central Excise duty on LED lights was reduced from 8 per cent to 4 per cent to promote their use. The basic component of these lights viz. the LED attracts an excise duty (hence, CVD) of 10 per cent and a special CVD of 4 per cent. The excise duty on LEDs is being reduced to 5 per cent and special CVD is being fully exempted.

172. The solar lantern enables our countrymen in far-flung villages to partake of developments in green technology. The basic customs duty on such lanterns is being reduced from 10 per cent to 5 per cent. Basic customs duty on a few more inputs used in the manufacture of solar modules/cells is being reduced to Nil.

173. Environmental considerations demand promotion of laundry soaps which conserve water and are gentle on the soil. To this end, full exemption from basic

customs duty is being provided to Crude Palm Stearin for use in the manufacture of laundry soap.

174. Pre-tanning or tanning processes in the leather industry use chemicals which are pollutants. To encourage use of green processes, full exemption from basic excise duty is being granted to enzyme based preparations for pre-tanning.

Infrastructure

175 Capital goods imported for the expansion of existing mega or ultra mega power projects enjoy a concessional basic customs duty of 2.5 per cent and full exemption from CVD. This creates a disability for the domestic suppliers who are required to pay Central Excise duty on supplies to such projects. I propose to correct this anomaly by providing a parallel excise duty exemption.

176. Bio-based asphalt is an emerging, green technology for the surfacing of roads. Full exemption from basic customs duty is being extended to bio-asphalt and specified machinery for its application in the construction of national highways. Tunnel-boring machines required for the construction of highways are also being included in this exemption.

Other Proposals

177. Works of art and antiquities are exempt from customs duties when imported for exhibition in a public museum or national institution. In recent years, many organisations have joined the cause of promoting and popularising both traditional and contemporary art. Some of them have been active in locating heritage works of Indian art and antiquities in foreign countries and bringing them back home. To encourage such initiatives, I propose to expand the scope of this exemption for works of art and antiquities to also apply to imports for exhibition or display, in private art galleries or similar premises that are open to the general public. Department of Culture will notify details of the scheme separately.

178. Full exemption from import duty is available to spares and capital goods required for ship-repair units. This exemption is being extended to imports by ship owners too.

179. The concessional basic customs duty of 5 per cent and CVD of 5 per cent, presently applicable to high-speed printing presses imported by newspaper establishments is being extended to mailroom equipment.

180. The Indian film industry has represented that colour, unexposed jumbo rolls of cinematographic film are not manufactured domestically and have to be imported. I propose to exempt jumbo rolls of 400 feet and 1000 feet from CVD by providing full exemption from excise duty.

181. I propose to provide outright concession to factory-built ambulances in place of the existing refund-based concession from excise duty. A refund-based concession is available to taxis having a seating capacity

not exceeding 7 persons including the driver. I propose to extend this to vehicles up to a seating capacity not exceeding 13 persons including the driver.

182. Some of the other relief measures that I propose are:

- Reduction in basic customs duty on raw pistachio from 30 per cent to 10 per cent;
- Reduction in basic customs duty on bamboo for agarbatti from 30 per cent to 10 per cent;
- Reduction in basic customs duty on lactose for the manufacture of homeopathic medicines from 25 per cent to 10 per cent; and
- Reduction in central excise duty on sanitary napkins, baby and adult diapers from 10 per cent to 1 per cent.

183. My proposals relating to customs and Central Excise are estimated to result in a net revenue gain of ₹ 7,300 crore for the year.

VIII. Service Tax

184. The actual collections of Service Tax do not reflect the full potential of this sector. While retaining the standard rate of service tax at 10 per cent, I seek to achieve a closer fit between the present service tax regime and its GST successor by :

- Bringing in a few new services into the tax net to expand the tax base while ensuring that the impact is predominantly on sections of society that have the ability to pay;
- Suitably expanding or rationalizing the scope of existing service categories;
- Rationalizing certain provisions relating to import of services and valuation;
- Modifying provisions of the Cenvat Credit scheme to achieve a more realistic balance between input credits and output tax and harmonising the provisions of the scheme across goods and Services;
- Rationalizing penal provisions to reinforce the message that honest taxpayers would be facilitated and deviants would be dealt with severely; and
- Adoption of Point of Taxation rules for services which would shift the basis for tax collection from "cash" towards "accrual" basis as with Central Excise duty.

185. I propose to levy service tax on the following new services:

- Hotel accommodation, in excess of declared tariff of ₹ 1,000 per day with an abatement of 50 per cent so that the effective burden is only 5 per cent of the amount charged;

- Service provided by air-conditioned restaurants that have license to serve liquor, by giving an abatement of 70 per cent. Thus, the effective burden will be 3 per cent of the bill.

186. I imposed service tax in 2010-11 on health check up or treatment. This levy has resulted in differential treatment between persons who make payments themselves and others where payments are made by an insurance company or a business entity. Thus, I propose to replace it with a tax on all services provided by hospitals with 25 or more beds that have the facility of central air-conditioning. Though the tax is on high-end treatment, I propose to sweeten the pill by an abatement of 50 per cent so that the actual burden is kept at 5 per cent of the value of service. I also propose to extend the levy to diagnostic tests of all kinds with the same rate of abatement. However, all Government hospitals shall be outside this levy.

187. I propose to raise the service tax on air travel by ₹ 50 in the case of domestic air travel and ₹ 250 on international journeys by economy class. I also propose to tax travel by higher classes on domestic sector at the standard rate of 10 per cent to bring it on par with journeys by higher classes on international air travel.

188. Services provided by life insurance companies in the area of investment are also proposed to be brought into tax net on the same lines as ULIPs. I propose to expand the scope of legal services to include services provided by business entities to individuals as well as representational and arbitration services by individuals to business entities. There shall, however, be no tax on services provided by individuals to other individuals.

189. There are certain other changes mainly by way of rationalisation or expansion in the scope of certain services or by plugging existing loopholes. I do not wish to take the valuable time of the House in further elaboration here.

190. The strength of a good value-added-tax lies in the free flow of the credit of the tax paid at the previous stage. Due to complexities, there have been many legal disputes on the availability of credit on a number of inputs or input services. These provisions are being rationalized by laying down clear definitions so that the scope of inputs and input services that are eligible and those that are not, is clear. Allocation of CENVAT credit to exempt and taxable goods and services is also being streamlined.

191. The number of assesseees in service tax has grown manifold. I find that a large number of them comprise

individuals or sole proprietors with small turnovers. Any audit at their premises tends to dislocate their activities for the duration of the audit. I therefore, propose to free all individual and sole proprietor taxpayers with a turnover upto ₹ 60 lakh from the formalities of audit. This will give relief to a large number of taxpayers. I also intend to give all assesseees with turnover upto ₹ 60 lakh, the benefit of 3 percentage points in interest on delayed payment.

192. In keeping with our thrust to encourage voluntary compliance, the penal provisions for Service Tax are being rationalised. A key component of this strategy would be to treat less harshly those who have maintained truthful records but have fallen short of discharging their tax liability. Simultaneously, deliberate evaders with unrecorded business transactions will be dealt with more severely. Similar changes are being carried out in Central Excise and Customs laws. The details of the provisions are in the Finance Bill.

193. My proposals relating to service tax are estimated to result in net revenue gain of ₹ 4,000 crore for the year.

194. Many experts have argued that it will be desirable to tax services based on a small negative list, so that many untapped sectors are brought into the tax net. Such an approach will be very conducive for a nationwide GST. I propose to initiate an informed public debate on the subject to help us finalise the approach to GST.

195. Copies of notifications giving effect to the changes in Customs, Central Excise and Service Tax will be laid on the Table of the House in due course.

196. My proposals on direct taxes are estimated to result in a revenue loss of ₹ 11,500 crore for the year. Proposals relating to indirect taxes are estimated to result in a net revenue gain of ₹ 11,300 crore, leaving a net loss of ₹ 200 crore in the Budget.

197. As an emerging economy, with a voice on the global stage, India stands at the threshold of a decade which presents immense possibilities. We must not let the recent strains and tensions hold us back from converting these possibilities into realities. With oneness of heart, let us all build an India, which in not too distant a future, will enter the comity of developed nations.

Madam Speaker, with these words, I commend the Budget to the House."

SHAKTIKANTA DAS, Addl. Secy. (Budget)